नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

वर्ष 03, अंक 351, नई दिल्ली, गुरुवार 19 फरवरी 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जिस इंसान के पास आशा होती है, वह कभी पराजित नहीं होता है!

02 दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम (108 नाम) माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे शीघ्र और...
06 विवाह के पंडाल में किताबों की प्रदर्शनी: एक नई और सराहनीय पहल
08 झारखंड में गुंडों की समानांतर सरकार: आदित्य साहु ,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

दिल्ली परिवहन आयुक्त की बाजदृष्टि:

प्रदूषण नियंत्रण या स्क्रैप डीलरों का अरबपति निर्माण?

सावधान फिर से परिवहन आयुक्त की बाज दृष्टि तत्पर फ्री में आपके वाहनों को उठवाने के लिए

संजय कुमार बाठला

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा समय सीमा पूरे वाहनों पर फिर से सख्ती का अभियान शुरू किया गया है, लेकिन कई अनियमित स्क्रैप डीलरों को प्राथमिकता देकर।

जिस कारण जनता का विश्वास डगमगा रहा है। यह अभियान प्रदूषण कम करने का दिखावा मात्र लग रहा है, जब तक पारदर्शिता सुनिश्चित ना हो।

पूर्व के काले अध्याय: दोहराई जा रही गलतियां दिल्ली जनता याद रखेगी कि विभाग ने प्रदूषण के नाम पर सीएनजी वाहनों और इलेक्ट्रिक रिक्शों तक को जब्त कर स्क्रैप डीलरों को सौंपा था, जो न्यायोचित नहीं था।

अब फरवरी 2026 में बिना पूर्व नोटिस के पुराने वाहनों (10 वर्षीय डीजल, 15 वर्षीय पेट्रोल) को जब्त करने का नया अभियान चला है।

विभागीय पिटों में सरकारी वाहन खड़े रहते हैं, लेकिन निजी वाहनों पर बल प्रयोग हो रहा है।

स्क्रैप डीलरों की अनियमितताएं: नोटिसों की अनदेखी विभाग उन डीलरों को फिर से वाहन सौंपने को तत्पर है जिन्हें पूर्व में कई नोटिस जारी हुए:

1. स्क्रैपिंग का ब्यौरा ना प्रस्तुत करना।
2. स्क्रैप मूल्य मालिकों या विभाग में जमा ना करना।
3. जब्त वाहनों को बाजार में बेचने के सबूत मौजूद होना।
4. लाइसेंस समाप्त या MoRTH से अनुमति प्राप्त ना होना।

यह डीलर ईएलवी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर भी दिल्ली परिवहन आयुक्त की मेहरबानी से सड़क परिवहन मंत्रालय की अनुमति के बिना सक्रिय हैं।

1. अनियमितता वाहन स्क्रैप डीलरो द्वारा स्क्रैप के लिए वाहन प्राप्त करने के बाद भी एसओपी के अनुसार स्क्रैप मूल्य जमा ना करना जिसका प्रभाव मालिकों को हानि और राजस्व चोरी जिस पर विभागीय कार्रवाई दिखाई गई शो-कॉज नोटिस, फिर भी उन्हीं को वाहन स्क्रैप करने के लिए नए वाहनों को देने की गतिविधि जारी
2. अनियमितता वाहन स्क्रैप डीलरो का लाइसेंस समाप्त प्रभाव अवैध स्क्रैपिंग जिस पर विभागीय कार्रवाई दिखाई गई नोटिस जारी होने के बाद भी अनदेखे और नए वाहनों को स्क्रैप करने की गतिविधि जारी
3. अनियमितता सीओडी की बाजार में बिक्री, जिसका प्रभाव सरकारी खजाने को नुकसान जिस पर विभागीय कार्रवाई दिखाई गई एसीबी जांच, सस्पेंड की धमकी फिर से रिज्यूम,

सही दिशा: पारदर्शी स्क्रैपिंग की मांग अभियान तब न्यायपूर्ण होगा जब

1. केवल प्रमाणित डीलरों को वाहन सौंपे जाएं जो 15 दिनों में स्क्रैप मूल्य जमा करें।
2. स्क्रैपिंग का डिजिटल सीओडी एवम्-वाहन स्क्रैप वीडियो वाहन पोर्टल पर अपलोड हो।
3. प्रदूषणकारी वाहनों और गैर कानूनी तरीके से सड़क पर चल रहे वाहनों पर प्राथमिकता हो, ना कि प्रदूषण-रहित वाहनों पर।

जनहित में परिवहन आयुक्त निर्देश दें:

* पहले डीलरों का हिसाब और प्रमाणित डीलरो का चयन फिर अभियान तेज करें।
* यह ना केवल दिल्ली में प्रदूषण रोकेगा, बल्कि जनता का भरोसा भी बहाल करेगा।

दिल्ली परिवहन विभाग से ग्रामीण सेवा चालकों की पुकार

राहत और सुधार की मांग: पेनल्टी माफी, नए परमिट और वन विंडो स्कीम जरूरी

संजय कुमार बाठला

ग्रामीण चालक और नेता चंदू चौरसिया ने पत्र लिखकर दिल्ली परिवहन विभाग से अनुरोध किया है

1. दिल्ली की सड़कों पर ग्रामीण सेवा की 6100 से अधिक गाड़ियां 15 वर्षों से जनता की सस्ती सेवा का माध्यम बनी रहीं, लेकिन कोरोना, तकनीकी देरी और कागजाती जटिलताओं ने इन्हें संकट में डाल दिया।
2. चालकों ने परिवहन विभाग से पेनल्टी माफी, कागजात सुधार और वन विंडो योजना की मांग की है।
3. यह कदम न केवल 6000 रोजगार बचाएगा, बल्कि प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक सेवा भी लाएगा।

पुरानी पेनल्टी का बोझः इलेक्ट्रिक परिवर्तन में बाधा 2010 में दिल्ली सरकार ने 6100+ ग्रामीण सेवा गाड़ियां सीएनजी पर उतारीं। पिछली सरकार के इलेक्ट्रिक परिवर्तन आदेश के बावजूद गाड़ियां सड़कों पर नहीं लौट पा रही।

मुख्य बाधाएं- चालान पेनल्टी और टूटे कागजात।

1. चालकों की मांगः दस्तावेज जांचकर राहत दें, ताकि 10-20 रुपये में सेवा शुरू हो सके।
2. लेंथ पूर्ति के तीन चरणः नई गाड़ियों का रास्ता साफ योजना 166 किमी रूटों पर शुरू हुई, लेकिन कई गाड़ियां नष्ट।
3. प्रस्तावित समाधानः

3.1 प्रथम अवसरः सही कागजात वालों को प्राथमिकता।

3.2 द्वितीय अवसरः कागजात मौजूद लेकिन गाड़ी खत्म वालों को।

3.3 तृतीय अवसरः नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए परमिट आवेदन।

यह दिल्लीवासियों को सस्ती सेवा देगा।

वन विंडोः चालकों की परेशानी दूर परिवहन विभाग में एक ही खिड़की पर कागजात जमा और समयसीमा बताने वाली योजना लागू हो। इससे भ्रष्टाचार रुकेगा और काम तेज होगा।

जनहित में फायदाः सस्ती सेवा, 6000+ रोजगार, शून्य प्रदूषण।

सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा।

(परिवहन विशेष के पाठकों से सुझाव आमंत्रित)

परिवहन विशेष के पंजाबी (गुरुमुखी ज्ञाता) और बंगाली पाठकों के लिए खुशखबरी

परिवहन विशेष दैनिक समाचार पत्र अब तक आपको हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में उपलब्ध हैं पर जल्द ही परिवहन विशेष प्रबंधक कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आपको पांच भाषाओं में उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा।

प्रबंधक मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है की

इसी महीने आरएनआई में बंगाली और गुरुमुखी भाषाओ में दैनिक समाचार पत्र छापने के लिए लाइसेंस अप्लाई कर दिया जाए।

आपको यह जान कर और भी प्रसन्नता होगी की अप्रैल से परिवहन विशेष दैनिक समाचार पत्र नोएडा के साथ एमपी, पंजाब और झारखंड से भी छपकर आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा।

झारखंड, पंजाब और एमपी में प्रिंटर के नाम फाइनल भी इसी बैठक में सर्वसम्मति से कर दिए गए हैं।

भारत देश में आपके द्वारा मिले प्यार और आशीर्वाद से तीन साल में ही यह समाचार पत्र एक भाषा से शुरू होकर पांच भाषाओं में पहुंचने का श्रेय प्राप्त कर रहा है। इसके लिए समस्त प्रबंधक मंडल के सदस्यों ने भारत की जनता खास तौर से समाचार पत्र को पसंद कर मांग करने वालो को हृदय से धन्यवाद दिया है।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) द्वारा - आयोजित एवं वैष्णवी फाउंडेशन के सौजन्य से - 'पूर्णता नि:शुल्क, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, स्वास्थ्य जाँच शिविर

आपकी तंदुरुस्ती हमारा ध्येय,

टोलवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित पूर्णत : निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

https://maps.app.goo.gl/f7TbV9rYetyW6ZqA7?g_st=aw

समय : 10:00 AM to 02:00 PM

* आंखों की जांच,
* रक्तचाप,
* मधुमेह जांच,
* मोतियाबिंद सर्जरी के साथ-साथ
* भारतीय लेंस की सुविधा

इस जांच शिविर मे पूरी तरह से नि:शुल्क प्रदान की जाएगी।

आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें तथा अपने सगे-संबंधियों और मित्रों को भी साथ लेकर आएँ और इस अवसर का लाभ उठाएँ।

विशेष जानकारी मोतियाबिंद सर्जरी के साथ-साथ भारतीय लेंस की सुविधा के लिए मरीज को अपने खर्चे पर

* बालाजी हॉस्पिटल
* लायन्स हॉस्पिटल

पहुंचना पड़ेगा, पर सर्जरी और भारतीय लेंस निशुल्क रहेगा।

इस जांच शिविर में निम्नलिखित अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टर्स एवम् अन्य की निगरानी में जांच,

1. डॉ मनोज कुमार दुबे,
2. रिशु भारद्वाज, एवं
3. विकास राय

जांच शिविर
दिनांक : 1 मार्च (रविवार) 2026

स्थान : गुरुद्वारा सिंह सभा, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, शिवाजी एन्क्लेव, दिल्ली 110027।

स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।
आपकी सेहत – हमारी प्राथमिकता।

निवेदक
पिंकी कुंडू, महासचिव
केके छाबड़ा उपाध्यक्ष
सुनीता शर्मा सचिव
अभिषेक राजपूत सचिव

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html |
tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार: AI और SIM Binding मिलकर साइबर अपराध पर कसेंगे नकेल।

पिंकी कुंडू

"SIM Binding केवल ताले को मज़बूत नहीं करता, बल्कि परतदार सुरक्षा से पूरे घर की रक्षा करता है।₹

SIM आधारित धोखाधड़ी—जैसे SIM Swap हमले और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से OTP चोरी—मोबाइल टेलीफोनी में सबसे लगातार बने रहने वाले खतरों में से हैं। हमलावर इस तथ्य का फायदा उठाते हैं कि अधिकांश प्रणालियाँ अब भी केवल मोबाइल नंबर को पहचान का आधार मानती हैं। यहीं पर SIM Binding तकनीक एक तकनीकी प्रतिरोधक उपाय के रूप में सामने आती है।

1. मज़बूत पहचान सत्यापन

- SIM Binding यह सुनिश्चित करता है कि हर मैसेजिंग अकाउंट एक सत्यापित SIM कार्ड से जुड़ा हो।
- AI सिस्टम लगातार असामान्य गतिविधियों की निगरानी करता है (जैसे एक ही SIM पर कई अकाउंट, या बार-बार SIM बदलना)।
- दोनों मिलकर पहचान की चोरी और गुमनाम धोखाधड़ी को कठिन बना देते हैं।

2. धोखाधड़ी पैटर्न की पहचान

- AI कॉल, संदेश और लेन-देन के उपयोग पैटर्न का विश्लेषण करता है।
- SIM Binding से पहचान SIM से जुड़ी रहती है, जिससे AI संदिग्ध गतिविधियों को आसानी से ट्रैक कर सकता है।
- उदाहरणः बल्क SMS स्कैम या संगठित फ़िशिंग प्रयासों का पता लगाना।

3. रियल-टाइम ब्लॉकिंग

- AI मॉडल तुरंत उन SIM को चिन्हित कर सकते हैं जो स्पैम या धोखाधड़ी में शामिल हैं।
- SIM Binding होने पर SIM को ब्लॉक करने से उससे जुड़े सभी अकाउंट अपने-आप निष्क्रिय हो जाते हैं।
- इससे अपराधियों को तुरंत रोकना संभव होता है।

4. अकाउंट हाईजैकिंग में कमी

- SIM Binding चोरी किए गए पासवर्ड से अकाउंट टेकओवर को रोकता है।
- AI अतिरिक्त सुरक्षा देता है—लॉगिन प्रयासों, डिवाइस बदलाव और लोकेशन मिसमैच की निगरानी करके।
- दोनों मिलकर OTP स्कैम और नकली लॉगिन से बचाव करते हैं।

5. कानून प्रवर्तन को लाभ

- SIM Binding एक ट्रेस करने योग्य पहचान रिकॉर्ड बनाता है।
- AI जांचकर्ताओं को SIM-लिंक्ड अकाउंट्स और धोखाधड़ी नेटवर्क को जोड़ने में मदद करता है।
- इससे साइबर अपराध मामलों में केस बनाना तेज़ और मज़बूत होता है।

*** समग्र प्रभाव**

- अपराधियों की गुमनामी खत्म होती है → SIM Binding उन्हें सत्यापित पहचान से जोड़ता है।
- धोखाधड़ी नेटवर्क जल्दी उजागर होते हैं → AI संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाता है।
- नागरिकों का भरोसा बढ़ता है → डिजिटल भुगतान, मैसेजिंग और ई-कॉमर्स सुरक्षित होते हैं।

*** SIM Binding कैसे काम करता है**

- तकनीकी जोड़: केवल मोबाइल नंबर पर निर्भर रहने के बजाय, SIM Binding खाते की पहुँच को एक विशिष्ट SIM कार्ड, उपकरण या अद्वितीय नेटवर्क पहचानकर्ताओं से जोड़ता है।
- लॉगिन/लेन-देन पर सत्यापनः प्रणाली यह जाँचती है कि अनुरोध विश्वसनीय SIM/डिवाइस प्रोफ़ाइल से आ रहा है या नहीं।
- धोखाधड़ी का पता लगानाः यदि SIM को बिना अनुमति बदला गया है, क्लोन किया गया है, या पुनः जारी किया गया है, तो प्रणाली पहुँच को रोक सकती है, अलर्ट जारी कर सकती है या अतिरिक्त सत्यापन लागू कर सकती है।

*** परतदार सुरक्षा रणनीति**

- SMS OTP से दूरीः ऐप आधारित प्रमाणीकरण (जैसे ऑथेंटिकेटर ऐप्स) या हार्डवेयर समर्थित समाधान (जैसे सिक्योरिटी की, डिवाइस-बाउंड क्रिप्टोग्राफी)।
- निरंतर निगरानीः असामान्य लॉगिन या लेन-देन पैटर्न को पहचानने के लिए व्यवहार विश्लेषण और विसंगति पहचान।
- उपयोगकर्ता जागरूकताः नागरिकों को SIM Swap धोखाधड़ी, फ़िशिंग और सोशल इंजीनियरिंग तरीकों के बारे में शिक्षित करना।

*** बड़ा परिप्रेक्ष्य**

SIM Binding मोबाइल टेलीफोनी को सुरक्षित बनाने में प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वास्तविक लचीलापन परतदार सुरक्षा से आता है। जैसे एक मज़बूत ताला मूल्यवान होता है, लेकिन यह सबसे प्रभावी तब होता है जब इसे निगरानी, अलार्म और सतर्क सुरक्षा के साथ जोड़ा जाए। साइबर सुरक्षा में इसका अर्थ है कि मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण, निगरानी और जागरूकता मिलकर काम करें।

शहनाज़ हुसैन: आयुर्वेदिक सौंदर्य की वैश्विक अग्रदूत और महिला उद्यमिता की प्रेरणादायक प्रतीक

प्रश्न ----आपका सौन्दर्य और आयुर्वेद की तरफ झुकाब कैसे हुआ और दिल्ली में आपके प्रारम्भिक जीवन में शहनाज़ आयुर्वेद की नींव रखने में आपका विज़न क्या रहा /

शहनाज़ हुसैन -----जब एक युवा मॉडल की केमिकल आई लाइनर की बजह से आँखों की रौशनी चली गई तो मेरा दिल पसीज गया /

इस घटना से मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया जब मेने केमिकल युक्त सौन्दर्य प्रसाधनों की बजाय सुरक्षित हर्बल आयुर्वेदिक सौन्दर्य प्रसाधनों

की तलाश शुरू की जोकि शरीर और स्वास्थ्य के लिए बेहतर हों / मुझे लगा की

प्राचीन आयुर्वेदिक में बिद्यमान

बेशकीमती हर्बल जड़ी बूटियों के गुणों में सभी सौन्दर्य समस्याओं का सकारात्मक समाधान विद्यमान है /

और इसी से प्रेरणा पाकर मेने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को खोजना शुरू कर दिया और इनका सौन्दर्य प्रसाधनों में उपयोग शुरू कर दिया /

मैंने 5000 साल पुरानी भारतीय सभ्यता के गुणों को एक जार में भर कर बेचना शुरू कर दिया जिससे लोगों को जड़ी बूटियों के चमत्कारी

स्वास्थ्यप्रद गुणों का अहसास हुआ

प्रशन ----पुरुष प्रदान उद्योग जगत में एक महिला उद्यमी के रूप में आपने किस तरह चुनौतियों का सामना किया ?

शहनाज़ हुसैन ----जब मैंने उद्योग जगत में एक उद्यमी के तौर पर कदम रखा तो तब महिलाओं की परिवार में भूमिका मात्र चुलाह चौका संभालने तक ही थी / उस समय महिलाएं पति और परिवार में एक धुरी की तरह काम करती थी और उनका संसार परिवार तक ही सीमित था / लेकिन मैने महिला की ऐसी परिभाषा गढ़नी शुरू कर दी जो ऊँचे ख्वाव देखती हों और जिंदगी में कुछ कर पाने की तमन्ना रखती हों / इस तरह से मैंने रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ कर एक नए संसार में प्रवेश किया जहां महिलाएं आज़ादी और इज़त से रह सकती हैं और खुले में साँस ले सकें / इस तरह मेरी दुनिया को आयुर्वदिक आधारित सुरक्षित हर्बल सौन्दर्य उत्पादों को प्रदान करने की जीवन यात्रा शुरू हुई / उस समय मार्किट में केमिकल आधारित उत्पादों की बाढ़ से थी जिनका बाजार पर जबरदस्त अधिपत्य था /

इस तरह सुरक्षित सौन्दर्य उत्पादों की तलाश में अनेक महिलाओं के लिए मैं पथ प्रदर्शक बनी और स्वास्थ्य बर्धक उत्पादों की खोज करने बाली महिलाओं में एक आशा की किरण जगी जिससे लोगों में सौन्दर्य के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा /

प्रश्न ---आप प्राचीन आयुर्वेद को सौन्दर्य की आधुनिक जरूरतों से कैसे जोड़ती हैं

शहनाज़ हुसैन -----आयुर्वेद में त्वचा और बालों से जुडी सभी सौन्दर्य समस्यायों का प्रकृतिक समाधान मौजूद है / आयुर्वेद के सिद्धान्त के अनुसार स्वास्थ्य शरीर में दोष(त्रिदोष) सन्तुलित होते हैं जिससे त्वचा और बाल सुन्दर दिखते हैं / इसलिए सही मायनों में सुन्दरता का मतलब संतुलित (त्रिदोष) के माध्यम से सुन्दर त्वचा ग्रहण करना है न की सौन्दर्य उत्पादों की मोटी परत लेपने से /मैने हर्बल उत्पादों की लम्बी श्रंखला तैयार की है जिसमे केमिकल कतई नहीं हैं जिन्हे बनस्पति / बगीचों के घटकों , प्रकृतिक जड़ी बूटियों , पौधों के अर्क , सुगन्धित तेलों से बनाया गया है जो पूरी तरह स्वास्थ्य बर्धक हैं और उनके उपयोग से प्रकृतिक तौर पर निखार उभर कर सामने आता है / आधुनिक सौन्दर्य जरूरतों जैसी कोई डिमांड नहीं है बल्कि अब लोगों का समग्र

(होलिस्टिक) जीवन शैली और वैलनेस आधारित सौन्दर्य उत्पादों के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है / अब महिलाएं उनकी त्वचा के माध्यम से उनके रक्त में जा रहे सौन्दर्य उत्पादों के संघटकों के प्रति संजीदा हो रही हैं / अब ग्राहक प्रकृतिक संघटकों पर आधारित सौन्दर्य उत्पादों के प्रति संजीदा हो रहे हैं और आयुर्वेद आधारित उत्पादों को ही बरीयता प्रदान कर रहे हैं और यहीं मेरी ताकत है क्योंकि मैं इसी लाइन में पिछले 50 सालों से हूँ और मेरी यह यात्रा निरन्तर आगे बढ़ती जा रही है /

प्रश्न --आपने सिग्नेचर ट्रीटमेंट / उत्पाद बाजार में उतारे हैं / इनके पीछे का आयुर्वेदिक विज्ञानं क्या है ?

शहनाज़ हुसैन -----यह कीमती जड़ी बूटियों से एकत्रित प्लांट स्टेम सेल हैं जिन्हें बैज्ञानिक बिधियों से उत्पादों का स्वरुप दिया गया है और यह चेहरे की झुर्रियों को रोकने और जवां दिखने में सहायक होते हैं / जड़ी बूटियों के गुणों से यह स्किन सेल को पुनर्जीवित करके नई शक्ति प्रदान करते हैं , त्वचा की इलास्टिसिटी को मूल रूप में बहाल करते हैं , चेहरे की छाइयों और झुर्रियों को कम करते हैं जिससे आप जवां और ऊर्जावान दिखते हैं / मैंने कैंसर रोगियों के लिए चेमोलिने उत्पाद लांच किया है जोकि हेयर आयल और त्वचा की क्रीम है / यह उत्पाद मैंने सामाजिक दायित्व के तौर पर उतारा है /यह विशेष्कर महिलाओं के लिए उतारा है जोकि

कीमो की बजह से बालों के खो जाने से भावुक तौर पर परेशान हो जाती हैं तथा मानसिक शारीरिक तौर पर परेशान हो जाती हैं / एक महिला ने मुझे इंग्लैंड से पत्र लिख कर बताया की कैसे केमोलिन क्रीम की मदद से उसकी त्वचा में सुधार आया और उसके परिवार जन और दोस्त उसको सराह रहे हैं / इससे उसका आत्म विस्वास और आत्म सम्मान बढ़ा /

यह उत्पाद समस्या की जड़ पर काम करते हैं और प्रकृतिक होने की बजह से एडाप्टोजेन हैं जोकि शरीर को शारीरिक ,मानसिक और पर्यावरणीय तनाव से निपटने में मदद करते हैं / इससे शरीर को पूरी तरह उपचार मिलता है और समस्या का जड़ से निदान भी हो जाता है /

प्रश्न ----महज एक ब्यूटी सैलून से शुरुआत करके आज विश्व भर में आपके 3000 से ज्यादा सैलून हैं / विश्व पटल पर आपकी सफलता का राज क्या है ?

शहनाज़ हुसैन ---------------
प्राकृतिक आयुर्वेदिक उत्पाद और उत्पादन में केवल शुद्ध हर्बल घटकों का प्रयोग मेरे ब्रांड की सबसे बड़ी शक्ति है / मेरा मानना है की हर्बल उपचार के माध्यम से ही सौन्दर्य समस्यायों की जड़ से इलाज किया जा सकता है और अब ज्यादातर लोग भी इसी बिचार से सहमत हो रहे हैं जिसकी बजह से लोग हमारे उत्पादों को पसन्द कर रहे हैं और यही मेरी ताकत है /

आज कल के उपभोक्ता स्वास्थ्य बर्धक उत्पादों को तरजीह दे रहे हैं / में सेहत और सौन्दर्य की कुंजी प्रदान करती हूँ /

प्रश्न ----आप आज की महिलाओं को क्या सलाह देंगी जोकि अपना उद्यम स्थापित करना चाहती हैं

शहनाज़ हुसैन -------अगर आप सफल उद्यमी बनना चाहती हैं तो सबसे पहले अपनी प्रतिभा में निखार लाएं और अपने रास्ते में आने बाली रुकाबटों और परेशानियों को जरूर ध्यान में रखें

यह ज्यादा महत्वपूर्ण है की आप अपना रास्ता चुने और पथ प्रदर्शक बनें न की भीड़ का हिस्सा बने / अगला कदम अपनी सफलता का ब्लू प्रिंट तैयार करें और अपनी मंजिल पाने के लिए अपना रास्ता तय करें / बेजोड़ बने और किसी की कॉपी न करें / मजबूत रहिये और आगे बढ़ने की सुदृड़ इच्छा सकती रखिये / जहाँ जरूरत हो बहां सीखने से परहेज मत करिये ।

लगातार नींद आती है? काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है? उदास, कमज़ोर, पूरे दिन थका हुआ?

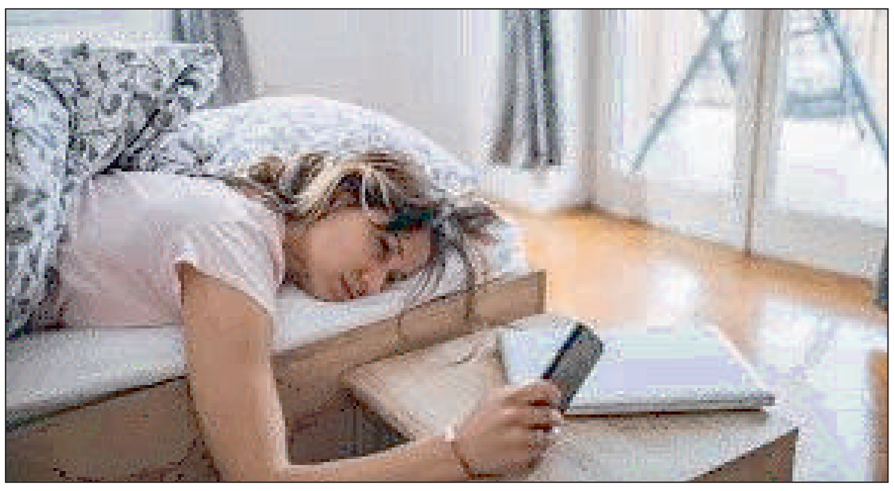

पिंकी कुंडू

अगर आपको ऐसा लगता है, तो यह मैसेज आपके लिए है।

यह "सिर्फ़ थकान" नहीं है यह शरीर की चेतावनी है!

* आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और आप इसे नज़रअंदाज़ कर रहे हैं।

इसके क्या कारण हो सकते हैं?

* नींद पूरी नहीं होती,
* रात में मोबाइल, टेंशन, ख्याल,
* दिमाग थक जाता है
* शरीर दिन भर आपका साथ नहीं देता

बहुत ज़्यादा खाना

* भारी खाना = शरीर भारी
* पाचन खराब हो जाता है
* आलस बढ़ता है

एक्सरसाइज़ की कमी

30 मिनट का समय नहीं?

* ब्लड सर्कुलेशन धीमा
* उत्साह बिल्कुल नहीं

प्रोटीन की कमी दूध, दही, अंडे, फल, नट्स नहीं? शरीर कमज़ोर

लगातार थकान बहुत ज़्यादा चीनी = बहुत ज़्यादा आलस

* मीठी चीज़ें कुछ देर के लिए खुशी देती हैं बाद में शरीर कमज़ोर हो जाता है
* हीमोग्लोबिन कम होना चक्कर आना, सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ़
* खून की कमी एक बड़ा कारण है स्ट्रेस, काम, घर, ज़िम्मेदारियाँ,
* दिमाग़ थक जाता है
* शरीर भी हार जाता है

क्योंकि दौलत, खुशी और ज़िंदगी तभी मिलेगी जब आपकी हेल्थ होगी!

आज ही फैसला लें – आपका शरीर आपका है, आपकी ज़िम्मेदारी भी आपकी है!

हेल्थ केयर: घरेलू नुस्खे, "लौंग"

यह घरेलू नुस्खे गांवों/पुरानी परंपराओं में अपनाए जाते हैं, इन्हें इस्तेमाल करना है या नहीं, यह आप पर निर्भर है।

इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है लौंग में मौजूद कमाल का इंग्रीडिएंट, यूजेनॉल कई नुकसान दायक बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के खिलाफ बहुत असरदार है। लौंग की एंटी - वायरल और ब्लड प्यूरिफाई करने की क्षमता खून में टॉक्सिसिटी को कम करती है और व्हाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करके बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाती है।

शरीर के दर्द और सूजन को कम करता है लौंग में मौजूद यूजेनॉल में मज़बूत एंटी - इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और यह शरीर में पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके दर्द को कम करने में मदद करता है। लौंग का तेल या एक्सट्रैक्ट आर्थराइटिस, सूजन और आम तौर पर किसी भी दर्द से राहत देता है। दांत दर्द से राहत देता है लौंग का तेल अपने जर्मिसाइडल गुणों के कारण दांतों के दर्द, दांत दर्द, मसूड़ों के दर्द और मुंह के छालों के लिए एक असरदार उपाय है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार लौंग के तेल को डेंटल एनेस्थेटिक के रूप में मंज़ूरी दी गई है।

लो ब्लड प्रेशर

पिंकी कुंडू

लो ब्लड प्रेशर अचानक चक्कर, कमजोरी या बेहोशी? जानिए 10 असरदार उपाय अगर आपको बार - बार चक्कर आना, ठंडा पसीना, धुंधला दिखना या अचानक कमजोरी महसूस होती है, तो यह लो ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है। लोग अक्सर हाई बीपी से डरते हैं, लेकिन लो बीपी भी उतना ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे दिल और दिमाग तक रक्त की सप्लाई कम हो जाती है।

लो ब्लड प्रेशर के सामान्य कारण

* लंबे समय तक भोजन न करना या उपवास
* डिहाइड्रेशन (पानी की कमी)
* अत्यधिक थकान, तनाव या गर्मी
* एनीमिया (खून की कमी)
* थायरॉयड, हृदय या हॉर्मोन असंतुलन
* कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट या बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत

लो बीपी के लिए 10 असरदार आयुर्वेदिक उपाय

1. किशमिश दूध रात में 10–12 किशमिश भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं और दूध पिएँ — यह रक्त की गुणवत्ता बढ़ाता है।
2. तुलसी पत्ते + शहद 5 तुलसी पत्तों का रस और 1 चम्मच शहद सुबह लें — बीपी संतुलित करता है।
3. नमक वाला पानी 1 गिलास पानी में चुटकीभर सेंधा नमक — तुरंत राहत देता है।
4. कॉफी या काली चाय कभी - कभी एक कप लेने से बीपी बढ़ता है, लेकिन रोज़ न लें।
5. सौंफ और मिश्री का पानी 1 चम्मच सौंफ + ½ चम्मच मिश्री गर्म पानी में — ऊर्जा बढ़ाता है।
6. मुनक्का और बादाम टॉनिक रात को 5 मुनक्का और 2 बादाम भिगोकर सुबह दूध के साथ लें — नसों को पोषण देता है।
7. मुलेठी पाउडर ½ चम्मच गुनगुने पानी में — एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय करता है।
8. नींबू - शहद पेय एक गिलास पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद — इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है।
9. दालचीनी + अदरक काढ़ा रक्त प्रवाह तेज करता है और शरीर को गर्म रखता है।
10. आयुर्वेदिक औषधियाँ

* अरविंदासव – हृदय बलवर्धक
* अश्वगंधारिष्ट – कमजोरी व तनाव में उपयोगी
* दशमूलारिष्ट – वात दोष शांत करता है

इन्हें सुबह-शाम पानी के साथ लें।

जीवनशैली और योग

* श्वासन, भ्रामरी, प्राणायाम करे
* 7 – 8 घंटे नींद लें
* लंबे समय तक खाली पेट न रहें
* हल्की वॉक करें, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा

कब डॉक्टर से मिलें?

1. बार-बार बेहोशी या तेज चक्कर आएँ
2. बीपी लगातार 90/60 से नीचे रहे
3. दिल की धड़कन बहुत धीमी या अनियमित हो।

'रिकेट्सिया' इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया

रिकेट्सिया एक तरह का ज़रूरी इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया है जो मुख्य रूप से इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड्स जैसे कि टिक, जूँ, पिस्सू और माइट्स के काटने से इंसानों में फैलता है। ये बैक्टीरिया दुनिया भर में कई तरह की बीमारियाँ पैदा करते हैं, जिन्हें एक साथ रिकेट्सियोसिस कहा जाता है।

बीमारियाँ और ट्रांसमिशन रिकेट्सियल बीमारियों को आम तौर पर स्पॉटेड फीवर ग्रुप और टाइफस ग्रुप में बांटा जाता है, जिसमें अलग-अलग तरह की बीमारियाँ खास बीमारियाँ पैदा करती हैं।

रिकेट्सिया रिकेट्सी: यह किस्म रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर (RMSF) का कारण है, जो अमेरिका में आम तौर पर टिक से होने वाली एक जानलेवा बीमारी है।

रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी: यह बैक्टीरिया एपिडेमिक टाइफस (जूँ से होने वाला टाइफस) का कारण है, जो इंसान के शरीर की जूँ से फैलता है।

रिकेट्सिया टाइफी: यह किस्म म्यूरिन टाइफस (पिस्सू से होने वाला टाइफस) पैदा करती है, जो पिस्सुओं से फैलता है।

रिकेट्सिया कोनोरी: यह जीव मेडिटेरेनियन स्पॉटेड फीवर (या दूसरे स्पॉटेड फीवर) के लिए ज़िम्मेदार है, जो टिक से फैलता है और यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है।

रिकेट्सिया अकारी: यह प्रजाति रिकेट्सियलपॉक्स का कारण बनती है, जो घर के चूहे के माइट्स से फैलता है।

आम लक्षण रिकेट्सियल इन्फेक्शन के लक्षण अक्सर नॉन - स्पेसिफिक होते हैं, जो एक्यूट फीवर वाली बीमारी जैसे होते हैं, और आमतौर पर इन्फेक्शन के 4 से 10 दिन बाद दिखाई देते हैं। मुख्य लक्षणों में शामिल हैं:

1. अचानक बुखार आना
2. तेज़ सिरदर्द
3. अस्वस्थता और थकान
4. रैश: एक खास मैकुलोपापुलर रैश आमतौर पर दूसरे लक्षणों के कुछ दिनों बाद होता है, जो अक्सर हाथ - पैरों (कलाई और टखनों) से शुरू होकर धड़ तक फैल जाता है।
5. मतली और उल्टी
6. मांसपेशियों में दर्द (मायल्जिया)
7. एस्चर: कुछ प्रजातियों में टिक या माइट के काटने की जगह पर एक गहरा, पपड़ी जैसा घाव बन सकता है।

डायग्नोसिस और इलाज.समय पर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा बीमारी और मौत हो सकती है।

डायग्नोसिस: डायग्नोसिस मुख्य रूप से क्लिनिकल होता है, जो लक्षणों और यात्रा या आर्थ्रोपोड के संपर्क में आने की पूरी हिस्ट्री पर आधारित होता है।

इसकी पुष्टि लैब टेस्ट से होती है, जैसे इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे या पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR), जिसके लिए अक्सर एक्यूट और कॉनवेल दोनों टेस्ट की ज़रूरत होती है।

डॉक्सीसाइक्लिन सभी उम्र के लोगों में रिकेट्सियल इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा इलाज है। इलाज जल्द से जल्द (बीमारी के पहले हफ़्ते में) शुरू कर देना चाहिए ताकि यह सबसे असरदार हो और गंभीर दिक्कतों से बचा जा सके, इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी (फ्लूइड मैनेजमेंट) भी बहुत ज़रूरी है।

*बीमारियाँ और ट्रांसमिशन रिकेट्सियल बीमारियों को आम तौर पर स्पॉटेड फीवर ग्रुप और टाइफस ग्रुप में बांटा जाता है, जिसमें अलग-अलग तरह की बीमारियाँ खास बीमारियाँ पैदा करती हैं। रिकेट्सिया रिकेट्सी: यह किस्म रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर (**RMSF**) का कारण है, जो अमेरिका में आम तौर पर टिक से होने वाली एक जानलेवा बीमारी है।*

पिंकी कुंडू

दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम (108 नाम) माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे शीघ्र और प्रभावी उपाय

दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम वह स्तोत्र है, जिसमें माँ दुर्गा के 108 दिव्य नामों का स्मरण किया जाता है। शास्त्रों में माना गया है कि नाम - स्मरण सीधे देवी तत्व से जुड़ता है, इसलिए यह साधना सरल होते हुए भी बहुत गहरी और प्रभावशाली मानी जाती है।

जब साधक श्रद्धा के साथ इन 108 नामों का जाप करता है, तो मन धीरे-धीरे एकाग्र होता है और माँ दुर्गा की कृपा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगती है। यह स्तोत्र विशेष रूप से उनके लिए उपयुक्त है, जो कठिन कर्मकांड नहीं कर पाते लेकिन देवी की अनुकम्पा चाहते हैं।

पूजन का सरल तरीका इस अष्टोत्तर शतनाम के जाप के साथ माँ दुर्गा का पंचामृत से स्नान / अभिषेक भी किया जा सकता है। पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और शक्कर) से किया गया स्नान साधना की शुद्धता और प्रभाव दोनों को बढ़ाता है। यदि पंचामृत उपलब्ध न हो, तो शुद्ध जल से स्नान कराकर भी यह साधना की जा सकती है।

शतनाम का जाप करें। जाप के समय मन को शांत रखें और प्रत्येक नाम के साथ माँ दुर्गा का स्मरण करें। यदि समय और सामर्थ्य हो, तो 21 या 108 बार जाप भी किया जा सकता है।

सकते हैं। घी या तिल मिश्रित हवन सामग्री से, "स्वाहा" के साथ नाम लेकर आहुति देने से साधना का प्रभाव और गहरा हो जाता है। यह प्रयोग विशेष रूप से गृह - शांति, बाधा - निवारण और देवी कृपा के

स्थिरता आती है, नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और भीतर एक सुरक्षा - भाव विकसित होता है। यह साधना धीरे - धीरे साधक को देवी के संरक्षण का अनुभव कराती है।

घर में नकारात्मक ऊर्जा है? सरल तंत्र से तुरंत दूर करे

पिंकी कुंडू

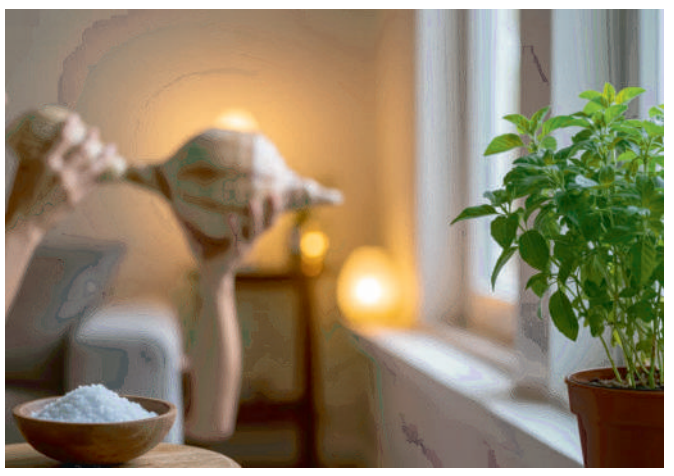

प्रिय पाठकों, क्या आपके घर में भी निम्नलिखित हालात हैं?

- बिना वजह झगड़े बढ़ जाते हैं
- मन भारी - भारी रहता है, नींद नहीं आती
- पैसों की तंगी, काम रुकना, स्वास्थ्य बिगड़ना
- घर में घुसते ही भारीपन महसूस होता है
- बच्चे चिड़चिड़े, रिश्ते खराब

यह सब संकेत घर में नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र - बाधा/नजर का असर है!

लेकिन घबराओ मत! आज हम आपको तंत्र शास्त्र के ऐसे पावरफुल और आसान उपाय बता रहे हैं जो घर को 7 - 21 दिनों में पूरी तरह शुद्ध कर देते हैं। यह उपाय हजारों ने आजमाए हैं और चमत्कार देखा है!

तंत्र से घर की नकारात्मक ऊर्जा हटाने के उपाय।

1. लोबान - गुग्गल की धूप (सबसे तुरंत असर वाला) रोज सुबह - शाम लोबान या गुग्गल जलाओ। धुएं को घर के हर कोने में फैलाओ (खासकर बेडरूम, किचन और मुख्य द्वार पर)।

* मंत्रः ॐ हं हनुमते नमः या
* ॐ कालभैरवाय नमः
* 11 बार बोलते हुए धूप दिखाओ।

नकारात्मकता जैसे धुआं उड़कर बाहर चली जाती है!

2. नमक का तांत्रिक कवच

- पोछा लगाते समय पानी में सेंधा नमक या समुद्री नमक डालो।
- घर के 4 कोनों में एक - एक कटोरी में नमक रखो (हर रविवार बदलते रहो, पुराना नमक बहते पानी में बहा दो)।

* नमक नकारात्मक ऊर्जा सोख लेता है – घर हल्का और शांत हो जाता है!

3. नींबू-मिर्च का सुरक्षा तंत्र मुख्य द्वार पर 7 हरी मिर्च + 1 नींबू को लाल धागे से बांधकर टांग दो। हर शनिवार बदलते रहो।

* यह नजर, तंत्र और बुरी नीयत से 100% बचाव करता है!

4. हनुमान या कालभैरव मंत्र जाप रात को सोने से पहले 108 बार जपोः ॐ नमो भगवते हनुमते नमः या ॐ कालभैरवाय नमः

* घर में हनुमान जी या भैरव की छोटी फोटो रखकर दीपक जलाओ। शत्रु शक्तियां भाग जाती हैं!

5. कपूर + लौंग का स्पेशल धूप 2 - 3 लौंग + कपूर को गाय के गोबर के उपले पर जलाओ (या साधारण अगरबत्ती स्टैंड पर)।

* धुआं घर में घुमाओ – तंत्र बाधा और भारी ऊर्जा जड़ से खत्म! यह उपाय बहुत पावरफुल है।

हनुमान जंजीरा एक अदृश्य जंजीर

पिंकी कुंडू

हनुमान जंजीरा एक अदृश्य जंजीर
जिससे लगती है भूत प्रेत को मार,
किसी भी मंगलवार शनिवार से प्रारंभ कर सकते है।

गुरु आज्ञा से करे तो पूर्ण लाभ मिले, हनुमान जी के सामने घी या चमेली का दीपक लगाकर, लाल वस्त्र धारण करके, लड्डू गुड चने का भोग लगाए,

इसके बाद 5 माला जाप करना है 21 से 41 दिन, जाप के बाद एक माला का हवन करना है, गुगल गुड घी पंचमेवा लौंग आदि सामग्री से, हवन रोज करना है।

जंजीरा जागृत होने लगेगा, किसी पर कोई ऊपरी बाधा हो उसकी आंखों मै देख कर या कंडे की रख उसके माथे पर लगाकर यह जंजीरा पढ़ने लगे, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आनद होगी वह बोलना शुरू कर देगी, किसने भेजा कहा से लगी सब बताएगी।

बाद मै हवन करदे उस व्यक्ति के सामने अर्जी लगाकर, और एक नारियल पर 11 बार मंत्र पढ़ कर सिर से उल्टा उतर कर बहते पानी मै बहा दे, बाधा समाप्त हो जाएगी, गुरु बनाकर ही साधना करे, गुरु ही आपको बंधन करना खोलना गुप्त चीजें बताते है

जंजीरा: ॐ हनुमान पहलवान पहलवान, बरस बारह का जबान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान अंजनी का पूत, राम का दूत, छिन में कीलौ नौ खंड का भूत, जाग जाग हड़मान (हनुमान) हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटाडग डेरू उमर गाजे, वज्र की कोठड़ी ब्रज का ताला आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सींण, अजरा झरे भरया भरे, ई घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हड़मान (हनुमान) करें।

जीवन केवल अधिकारों के पीछे भागने का नाम नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने की एक सुंदर साधना

संजय कुमार बाठला

हर व्यक्ति भगवान श्री राम का नाम जानता है, घरों में तस्वीरें, त्योहारों में उनका स्मरण और मंचों पर रामलीला करते है।

इन्हीं सब के बीच कुछ लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि रामायण लिखी क्यों गई,

क्या रामायण का उद्देश्य केवल रावण का वध बताना था? क्या केवल एक युद्ध को आधार बनाकर इसकी रचना की गई थी?

* या इसके पीछे ऐसा कोई गहरा ज्ञान छिपा है जो सीधे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है?

यदि हम सत्य को समझने का प्रयास करें तो पाएँगे कि रामायण की शुरुआत किसी राजदरबार या किसी युद्धभूमि से नहीं इसकी शुरुआत एक टूटे हुए हृदय से हुई और वह हृदय था महर्षि वाल्मीकि का।

एक दिन सुबह गंगा के पास बहने वाली तमसा नदी के एक अत्यंत निर्मल जल वाले तीर्थ पर मुनि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ स्नान के लिए गए। मार्ग में उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। दोनों प्रेम में मग्न थे। तभी एक व्याध ने बाण चलाया और नर पक्षी को मार गिराया। बाण लगते ही वह धरती पर गिर पड़ा। अपने साथी को मृत देखकर मादा क्रौंच का विलाप जंगल में गूंज उठा। वह तड़प रही थी, पुकार रही थी, जैसे आकाश से न्याय मांग रही हो।

उस क्षण वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर उठा। उनके भीतर जो वेदना उठी, वह शब्द बनकर बाहर आई। उनके मुख से स्वतः यह श्लोक निकला—

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शास्वती समा।
यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।।

अर्थात- निषाद। तुझे कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली।

यह शाप केवल एक शिकारी को नहीं था, यह अन्याय के विरुद्ध पहली संवेदनशील आवाज़ थी।

यही संसार का पहला श्लोक माना गया। करुणा ने जब शब्द का रूप लिया, तभी काव्य का जन्म हुआ। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम उसी छंद में उस पुरुष की कथा लिखो जो मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण है और इस प्रकार रची गई वाल्मीकि रामायण।

अब प्रश्न यह है कि उस कथा को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? रामायण इसलिए नहीं लिखी गई कि लोग केवल भगवान की पूजा करें। वह इसलिए लिखी गई कि मनुष्य यह समझ सके कि जीवन को कैसे जिया जाता है।

जब समाज में मर्यादाएँ टूटने लगें, जब शक्ति अहंकार बन जाए, जब संबंध स्वार्थ में बदल जाएँ, तब एक आदर्श की आवश्यकता होती है। रामायण उसी आदर्श की स्थापना है।

श्रीराम को केवल भगवान कह देना आसान है, लेकिन उन्हें एक मनुष्य के रूप में समझना आवश्यक है। उन्होंने भी दुख सहा, वनवास स्वीकार किया, पिता का वचन निभाने के लिए राज्य त्याग दिया। पत्नी का वियोग सहा, अपने ही लोगों की आलोचना झेली, फिर भी धर्म की रेखा कभी पार नहीं की। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया।

रामायण का उद्देश्य केवल रावण का वध दिखाना नहीं था। रावण तो एक प्रतीक था — अहंकार का, शक्ति के दुरुपयोग का, ज्ञान होते हुए भी विवेक खो देने का। रामायण हमें यह बताती है कि बाहरी रावण से पहले हमें अपने भीतर के रावण को पहचानना होगा।

जब हम जीवन में अन्याय देखते हैं, जब हमें लगता है कि सत्य दब रहा है, जब परिवारों में दूरी बढ़ रही है, तब रामायण हमें स्मरण कराती है कि धर्म कठिन हो सकता है, पर असंभव नहीं। त्याग पीड़ा दे सकता है, पर अंततः वही आत्मा को शांति देता है।

रामायण इसलिए अस्तित्व में आई ताकि आने वाली पीढ़ियाँ यह न भूलें कि

जीवन केवल अधिकारों का नाम नहीं है, वह कर्तव्यों का भी नाम है।

वह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि संयम की परीक्षा है।

* वह केवल विजय का उत्सव नहीं, बल्कि त्याग की साधना है।

जब तक मनुष्य के जीवन में संघर्ष रहेगा, जब तक सही और गलत के बीच द्वंद्व रहेगा, तब तक रामायण की आवश्यकता बनी रहेगी, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है।

रामायण संदेश - रामायण हमें सिखाती है कि जीवन केवल

अधिकारों के पीछे भागने का नाम नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने की एक सुंदर साधना है।

बीज मंत्र का राजः 'क्रीं', 'ह्रीं', 'श्रीं' – शब्द नहीं, ब्रह्मांड कोड!

संजय कुमार बाठला

कल्पना करो कि प्राचीन तंत्र ग्रंथों में छिपे बीज अक्षर, जिन्हें जपते ही देवता की ऊर्जा सीधे तुम्हारे शरीर में उतर आए – और अचानक जीवन बदल जाए!

यह है वह तीन शक्ति बीज – महाकाली, महामाया और महालक्ष्मी की मूल ध्वनि। ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ सुनते हैं यह दैवीय कंपन है जो कुंडलिनी को जगाते, माया को काटते, और समृद्धि को बुलाते हैं।

1. क्रीं – महाकाली का प्रचंड बीज! उच्चारण का राज: "क्रीं" –

* "क" शिव की शुद्ध चेतना,
* "र" अग्नि का विस्फोट,
* "ई" माया की तीव्रता, और
* "ं" ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को बांधता है।

गूढ़ रहस्य: यह समय (काल) को नियंत्रित करने वाला मंत्र है।

* जप से भय, शत्रु, पुरानी बुरी आदतें – सब जड़ से जल जाते हैं!
* तंत्र में इसे क्रिया योग का मूल माना जाता है – कुंडलिनी जागृत होती है, निचले चक्र जलते हैं, और सिद्धियां खुलती हैं (त्रिकाल ज्ञान, अलौकिक रक्षा)।

जरूरी सूचना: बिना तैयारी जप करो तो बैकफायर हो सकता है – मानसिक तूफान! लेकिन सही गुरु से दीक्षा लेकर जपो तो... जीवन का हर डर गायब!

मंत्र पावर: शत्रु नाश, साहस, स्वास्थ्य, ट्रांसफॉर्मेशन।

रोज 108 बार "ॐ क्रीं कालिकायै नमः" – और देखो चमत्कार!

2. ह्रीं – महामाया / भुवनेश्वरी का सोलर बीज!

* उच्चारण का राज: "ह्रीं" –
* "ह" शिव,
* "र" अग्नि,
* "ई" चेतना,
* "ं" अनंत शक्ति।

यह सर्वशक्तिमान मंत्र है – सूर्य ऊर्जा का प्रतीक!

गूढ़ रहस्य:

* हृदय चक्र (अनाहत) से जुड़ा ये मंत्र माया (भ्रम) को काटता है।
* जप से आंतरिक शांति, दिव्य प्रेम, और आकर्षण की शक्ति जागती है। तंत्र में इसे महादेवी का प्रणव कहते हैं – ये सृजन, पालन, संहार तीनों को कंट्रोल करता है!

जरूरी सूचना: जैन धर्म में भी "ह्रीं" अनंतता और तीर्थंकरों की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है! कल्पना करो – जपते ही तुम्हारा हृदय सूरज की तरह चमकने लगे!

मंत्र पावर: नकारात्मकता से मुक्ति, सौंदर्य, आकर्षण, उच्च चेतना।

"ॐ ह्रीं" अकेला जप – हृदय पर फोकस करो, और महसूस करो ऊर्जा!

3. श्रीं – महालक्ष्मी का प्रचुरता बीज!

* उच्चारण का राज: "श्रीं" –
* "श" शांति,
* "र" अग्नि,
* "ई" माया,
* "ं" समृद्धि का बिंदु।

गूढ़ रहस्य:

* यह चंद्र ऊर्जा और प्रचुरता का मंत्र है।
* जप से धन, ऐश्वर्य, सफलता – सब आकर्षित होता है!
* तंत्र में इसे धन - काम का मूल कहा जाता है – गरीबी और कमी को जड़ से मिटाता है।

जरूरी सूचना: लक्ष्मी चंचल हैं, लेकिन "श्रीं" जप से वो स्थिर हो जाती हैं! शुक्रवार को जपो तो दोगुना फल – व्यवसाय, करियर, वैवाहिक सुख सब संतुलित!

मंत्र पावर: धन प्राप्ति, व्यवसाय में बढ़ोतरी, सौंदर्य, खुशहाली।

"ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" – और देखो पैसे की बारिश!

तीनों का संयुक्त जादू: ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं – पांच महाशक्तियां एक साथ जागृत!

यह बीज सिर्फ ध्वनि नहीं – बीज है! जैसे बीज से वृक्ष उगता है, वैसे जप से जीवन फलता - फूलता है। लेकिन याद रखो: गुरु दीक्षा बिना मत छेड़ना – यह दिव्य संहिता है!

सही तरीका: "ं" को नाक से कंपन करो, जैसे "म" की गूंज।

सावधानी: पहले शांति मंत्र से शुद्धि करो, वरना ऊर्जा अधिभार हो सकती है!

आमजन को बेहतर और सुरक्षित आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता :एसडीएम

परिवहन विशेष न्यूज

निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप हों सड़क से जुड़े सभी कार्य

एसडीएम अभिनव सिवाच आईएएस ने अधिकारियों के साथ गांव जसौर खेड़ी से कुलासी रोड का किया निरीक्षण

बहादुरगढ़, 18 फरवरी। एसडीएम अभिनव सिवाच आईएएस ने बुधवार को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ गांव जसौर खेड़ी से कुलासी रोड का दौरा कर निर्माण एवं रखरखाव कार्यों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान सड़क की गुणवत्ता, साइड पटरी की स्थिति, जल निकासी व्यवस्था तथा यातायात सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का बारीकी से जायजा लिया।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क से जुड़े सभी कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किए जाएं और जहां कहीं भी मरम्मत अथवा सुधार की आवश्यकता हो, उसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक संकेतक एवं सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने को भी कहा।

एसडीएम ने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए, ताकि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो और परियोजना समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सके। उन्होंने दोहराया कि जहां पर भी सड़क उखड़ी हुई है, वहां से पैच वर्क कराया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए।

इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ राजेश तोमर और जेई बिजेंद्र मौजूद रहे।

जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आज

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 18 फरवरी। जनता की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा आज(19 फरवरी वीरवार)को जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय, झज्जर के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एडीसी जगनिवास करेंगे। इस दौरान एडीसी विभागों से संबंधित शिकायतें सुनेंगे और उपस्थित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देंगे, ताकि आमजन को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिल सके।

उपमंडल स्तर पर भी संबंधित लघु सचिवालय परिसरों में समाधान शिविर आयोजित होंगे। बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच (आईएएस), बेरी में एसडीएम रेणुका नांदल तथा बादली में एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता की अध्यक्षता में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जाएगा।

एडीसी ने कहा कि समाधान शिविर प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय में समाधान शिविर प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं, ताकि लोगों को एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान मिल सके।

केवल लाईसेंसशुदा कॉलोनियों में ही प्लाट खरीद करें नागरिक : एडीसी

गांव महाराणा और माछरोली में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई

झज्जर, 18 फरवरी। प्रशासन द्वारा दो गांव महाराणा और माछरोली में बगैर लाइसेंस व तय प्रक्रिया पूरी किए अवैध कॉलोनी काटे जाने के मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। एडीसी जगनिवास ने बताया कि गांव महाराणा के खसरा नंबर 94//19,20/1/1,20/1/2 और गांव माछरोली के खसरा नंबर 111//3,4 से जुड़े किसी भी प्रकार के सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड/एग्जीक्यूट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को उक्त अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन जारी न करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे केवल सरकार द्वारा वैध एवं स्वीकृत कॉलोनियों में ही मकान बनाने के लिए प्लाट खरीद सकते हैं। एडीसी ने कहा कि प्रशासन अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है।

प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी किसानों की आय, मिट्टी और पर्यावरण दोनों होंगे सुरक्षित : एसडीएम

एसडीएम रेणुका नांदल ने गांव पलड़ा में जिला स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला का किया शुभारंभ

जिला स्तरीय कार्यशाला में लगभग पांच सौ किसानों ने लिया भाग

बेरी (झज्जर), 18 फरवरी। निकटवर्ती गांव पलड़ा में बुधवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भूमि ऑर्गेनिक्स परिसर में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि एसडीएम रेणुका नांदल ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल खेती पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया। एसडीएम रेणुका नांदल ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, उत्पादन लागत में कमी आती है और किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत होती हैं। साथ ही यह खेती पद्धति पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहयोग दिया जा रहा है।

इस अवसर पर बीएओ डॉ. अशोक रोहिल्ला ने मुख्य अतिथि रेणुका नांदल का स्वागत करते हुए विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों से एग्रीस्टैक (फार्मर आईडी) बनवाने का आह्वान करते हुए कहा कि किसान बिना किसी भय और संकोच के अपनी फार्मर आईडी बनवाएं। इससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और अनुदानों का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एग्री स्टैक आईडी पूरी तरह से किसानों के हित में है। कार्यशाला के दौरान बागवानी, फिशरीज, एनिमल हसबेंडरी सहित अन्य संबंधित विभागों द्वारा अपने-अपने स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों के माध्यम से किसानों को विभागीय योजनाओं, अनुदानों, प्राकृतिक खेती से जुड़ी नवीन तकनीकों और सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी गई। किसानों ने इन स्टॉलों पर जाकर विशेषज्ञों से सीधे संवाद किया और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।

कार्यशाला में लगभग पांच सौ किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर बीडीपीओ राजाराम, एपीपीओ डॉ. भैयाराम, एसएमएस रमेश लांबा,तकनीकी अधिकारी डॉ रोहित वत्स,एएसओ कुलदीप सिंह, एईईओ राजीव चावला, बीटीएम संजय कुमार, डॉ यगदीप, एसए सतीश, सोमबीर, मंजू, कुलदीप,कोऑपरेटिव सोसायटी से सब-इंस्पेक्टर अजय मार्केट कमेटी सचिव विद्यासागर, एसडीओ डॉ. ऋषिपाल, एस.एन. कौशिक, बायोडाइवर्सिटी विभाग से कुसुम, एडवोकेट आशीष कादयान विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कानपुर में चाकू से गोद मारी भाजपा नेता को गोली, जारी आरोपियों की तलाश

सुनील बाजपेई

कानपुर। दुकान को लेकर पुरानी रंजश के चलते चाकू से गोदने के बाद भाजपा नेता को गोली मार दी गई।अस्पताल में उसकी हालत समाचार लिखे जाने तक गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस की चार टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

यह घटना रावतपुर थानाक्षेत्र के छपेड़ा पुलिया के पास हुईं। यहां मंगलवार की देर रात दुकान की रंजिश में तीन युवकों ने चाकुओं से गोदने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सोनू राठौर की पीठ पर गोली भी मार दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

भाजपा युवा मोर्चा का पूर्व जिला उपाध्यक्ष सोनू राठौर नवाबगंज के सिग्नेचर सिटी के पास रहते हैं। मां रज्जो देवी और भाई सौरभ ने बताया कि छपेड़ा पुलिया पर उनकी पूजन सामग्री की दुकान है।

परिजनों द्वारा मौके पर पहुंची पुलिस को दी गई जानकारी केमुताबिक मंगलवार की रात सोनू राठौर रावतपुर में एक शादी समारोह में गए थे। वहां से छपेड़ा पुलिया स्थित दुकान के पास से होकर आ रहे थे। इसी बीच साजन उर्फ रोहित, बाबा लाइट और अभिषेक ने अपने साथियों के साथ उसे जमकर पीटा। गोली मारने के बाद चाकुओं से गोद दिया।

पुलिस केमुताबिक उसके शरीर में सात से आठ चाकू के वार मिले हैं। पीठ पर भी गोली लगी है। एडीसीपी कपिल देव सिंह ने बताया दोनों पक्षों के बीच दुकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी के चलते मंगलवार की देर रात हमला किया।

एडीसीपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गई हैं। घटना की जानकारी पर कई भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए सर्किल का फोर्स तैनात कर दिया गया है। इस बीच डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी जांच करने मौके पहुंचे और फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय में 'गीता के माध्यम से नेतृत्व उत्कृष्टता' विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

गीता केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं है बल्कि आधुनिक नेतृत्व और प्रबंधन की अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या करने वाला दार्शनिक ग्रंथ है-प्रो . निरंजन कुमार

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति द्वारा 'गीता के माध्यम से नेतृत्व उत्कृष्टता' विषय पर दो दिवसीय 16-17 फरवरी को क्षमता संवर्धन कार्यशाला (कैपिसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप) का आयोजन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए आयोजित इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष प्रो. निरंजन कुमार ने बताया कि आज के वैज्ञानिक युग में दिल्ली विश्वविद्यालय की मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति द्वारा गीता जैसे धर्म ग्रंथ पर चार कोर्सेस बनाए गए हैं।पाठ्यक्रम निर्माण पर चर्चा करते हुए प्रो.निरंजन ने आगे कहा कि 'गीता केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं है;बल्कि आधुनिक नेतृत्व और प्रबंधन की अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या करने वाला दार्शनिक ग्रंथ है' ।उन्होंने बताया कि भारत के पहले गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर जर्मनी के विल्हेल्म हम्बोल्ट और शोपेनहावर, अमेरिका के राल्फ इमर्सन और हेनरी डेविड थोरो और इंग्लैंड के एल्डस हक्सले आदि अनेक दार्शनिक गीता की दार्शनिक उत्कृष्टता, सार्वभौमिक अपील और आध्यात्मिक गहनता से अत्यंत प्रभावित थे। प्रो. निरंजन ने कहा कि आज इन्टरनेट और एआई के समय में जहाँ सामूहिकता खत्म होती जा रही है ऐसे में गीता हमें स्व से पर की ओर अर्थात मनुष्यता की ओर ले जाती है। प्रो. कुमार ने कहा कि मूल रूप से हमारे भीतर एक

पशु बैठा होता है जो तामसिक होता है, और गीता हमें उस तमोगुण से सतोगुण की ओर लेकर जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण बच्चों के जीवन को सही दिशा देने में सहायक सिद्ध होंगे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार राज्य के डीजीपी डॉ. परेश सक्सेना ने गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता नेतृत्व के विविध आयामों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। महाभारत के विभिन्न पात्रों के माध्यम से उन्होंने गीता में निहित नेतृत्व क्षमता को विस्तार से समझाया। जो व्यक्ति समाज का आदर्श होता है।आम जनता उसका ही अनुसरण करती है और गीता व्यक्ति के बेहतर चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।शांति,त्याग, मृदुलता,निर्भयता एवं अहिंसा आदि गुण नेतृत्व के लिए अनिवार्य हैं जो गीता हमें आत्मसात करने की प्रेरणा देती है।आधुनिक नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांत जिन्हें आज पश्चिमी विचारधारा से जोड़ा जाता है उनके मूल तत्व गीता में पहले से ही स्पष्ट रूप में विद्यमान हैं।आज के समय में एक संतुलित समाज और समग्र नेतृत्व के निर्माण में गीता की प्रमुख भूमिका है।

कार्यशाला में प्रो.प्रभात मित्तल,प्रो.महिमा ठाकुर,प्रो. पंकज मिश्र,प्रो.रजनी साहनी,इस्कॉन के रोमी कुमार आदि ने भी संबोधित किया।

दिल्ली विश्वविद्यालय की मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति शिक्षकों के लिए इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन लगातार करती रहती है।

गौ सेवा का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व – डॉ. शंभू पंवार

पितृ पुण्य तिथि पर गौशाला में किया गौमाताओं का पूजन व भोग अर्पण

डॉ. शंभु पंवार

नई दिल्ली, 18 फरवरी। सनातन संस्कृति में गौ सेवा को सर्वोच्च स्थान बताते हुए प्रख्यात गौ सेवक, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, अंतरराष्ट्रीय लेखक एवं पत्रकार-विचारक डॉ. शंभु पंवार ने कहा कि गौमाता की सेवा से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि परिवार में सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा का वास होता है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में वर्णित है कि गौमाता में 33 करोड़ देवी-देवताओं का निवास होता है, इसलिए गौ सेवा स्वयं में एक महान पुण्य कार्य है। डॉ. पंवार ने ये विचार श्री कृष्ण गौ शाला में व्यक्त किए, जहां वे अपने पिताजी की पुण्य तिथि के अवसर पर गौमाताओं को दलिया का भोग अर्पित करने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गौ सेवा चार धाम यात्रा के समान फलदायी है। इससे पूर्वजों को शांति मिलती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। उन्होंने बताया कि वे वर्षों से एक अनूठी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, जिसके तहत अपने तथा परिवार के सदस्यों के जन्मदिवस, माता-पिता की पुण्य तिथि जैसे अवसरों पर गौशाला जाकर गौमाताओं को गुड़ व दलिया अर्पित करते हैं। यह परंपरा उनके लिए केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और संस्कारों का प्रतीक है। इस अवसर पर उनके अनुज विजय पंवार एवं पुत्र अभिषेक पंवार ने भी गौमाताओं को भोग अर्पित किया। डॉ. पंवार ने बताया कि वे जब भी गौशाला जाते हैं, अपने भाई, पुत्र एवं पौत्री को साथ ले जाते हैं, ताकि भावी पीढ़ी को सनातन संस्कृति में गौमाता के महत्व का बोध हो और यह परंपरा आने वाले समय में भी सतत रूप से चलती रहे। उल्लेखनीय है कि डॉ. शम्भु पंवार सामाजिक सरोकारों में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ-साथ एक समर्पित गौ सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं। उनका मानना है कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति की आत्मा है और समाज में नैतिकता, करुणा एवं सामूहिक कल्याण का आधार है।

'अखण्ड संडे' (इन्दौर) के वार्षिक महोत्सव में विशिष्ट अतिथि होंगे वृन्दावन के 'यूपी रत्न' डॉ. गोपाल चतुर्वेदी

परिवहन विशेष न्यूज

वृन्दावन। नगर के प्रख्यात साहित्यकार₹यूपी रत्न₹ डॉ. गोपाल चतुर्वेदी इन्दौर (मध्य प्रदेश) की प्रख्यात साहित्यिक संस्था ₹अखण्ड संडे₹ के स्थापना दिवस पर 19 फरवरी 2026 को सायं 04 बजे से आयोजित होने वाले ऑनलाइन वार्षिक महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे ।साथ ही वे संस्था के द्वारा प्रकाशित ₹अखंड काव्य धारा₹ नामक साझा काव्य संग्रह के छठे भाग का लोकार्पण भी करेंगे ।जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों के लब्ध-प्रतिष्ठ 131 कवियों की 263 रचनाएं संग्रहित हैं।

यह जानकारी ₹अखण्ड संडे₹ संस्था के संस्थापक अध्यक्ष मुकेश इंदौरी ने दी है ।साथ ही उन्होंने बताया है कि इस महोत्सव की अध्यक्षता प्रख्यात इतिहासकार नर्मदा प्रसाद उपाध्याय करेंगें और मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विलास दवे भाग लेंगे।

बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित हुईं मॉडल एवं समाज सेविका मीनू कुमार

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

दिल्ली ।पी न्यूज के द्वारा मॉडल एवं समाजसेविका मीनू कुमार को बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया ।ये जानकारी पी न्यूज के एडिटर ने दी ।मीनू कुमार एक सुप्रसिद्ध मॉडल एवं समाजसेविका है ।अनेक संस्थाओं से जुड़ी है ।उनका समाजसेवा के प्रति योगदान सराहनीय एवं अनुकरणीय है। मीनू कुमार मॉडलिंग के क्षेत्र में भी एक मुकाम बनाया है ।उनके साहित्य, समाज, मॉडलिंग, और एक्टिंग के प्रति किए गए कार्यों और उनके सराहनीय योगदान के लिए उनको इस अवॉर्ड के लिए चुना गया ।मीनू कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस अवॉर्ड के लिए पी न्यूज को थैंक यू ।मेरी जिम्मेदारी भी है कि मै और अच्छा करूं जिससे समाज को एक अच्छा संदेश जाए और लोग भी अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करे।

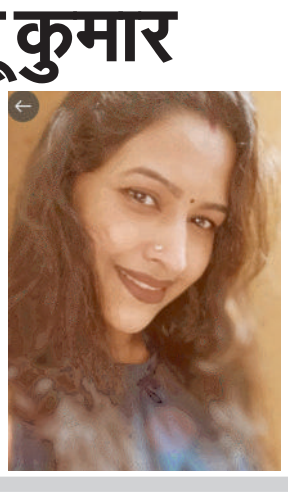

5 साल का हरित संकल्प: 19 फरवरी को विशेष समारोह में मनाया जाएगा पौधारोपण अभियान का सफर

संगिनी घोष

पर्यावरण संदेश को जनआंदोलन बनाने की पहल

शिवराज सिंह चौहान के अनोखे पौधारोपण संकल्प के पाँच वर्ष पूरे होने पर 19 फरवरी को नई दिल्ली के पूसा स्थित एपी शिंदे हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह पहल उनके उस संकल्प की याद दिलाती है जिसमें उन्होंने प्रतिदिन एक पौधा लगाने का लक्ष्य अपनाया था और इसे व्यक्तिगत आदत से जनभागीदारी अभियान में बदलने की कोशिश की।

ऐसे देखें तो, यह पहल सिर्फ पौधारोपण कार्यक्रम नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संदेश देती है।

'एक पौधा प्रतिदिन' अभियान का विचार

मंत्री का कहना रहा है कि पर्यावरण बचाने के लिए बड़े भाषणों से ज्यादा छोटे लेकिन नियमित कदम जरूरी हैं। इसी सोच के साथ शुरू हुआ "एक पौधा प्रतिदिन" संकल्प धीरे-धीरे लोगों की भागीदारी से व्यापक अभियान बन गया। आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम में पर्यावरण कार्यकर्ता, किसान प्रतिनिधि और युवा स्वयंसेवक भी शामिल होंगे।

नर्मदा से राष्ट्रीय मंच तक अभियान का विस्तार

इस हरित अभियान की शुरुआत क्षेत्रीय स्तर से हुई थी, लेकिन समय के साथ यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। समर्थकों का दावा है कि जनभागीदारी ने इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत पहल से आगे बढ़ाकर सामूहिक पर्यावरण आंदोलन का रूप दे दिया।

कार्यक्रम में क्या होगा खास

सूत्रों के अनुसार समारोह में पिछले पाँच वर्षों की उपलब्धियों, लगाए गए पौधों के आँकड़ों और भविष्य की पर्यावरण योजनाओं की प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता संदेश भी साझा किए जाएंगे।

यह पहल क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है

विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी चुनौतियों के दौर में जनभागीदारी आधारित अभियान ही स्थायी समाधान दे सकते हैं। नियमित पौधारोपण जैसे छोटे कदम लंबे समय में बड़ा प्रभाव डालते हैं।

ऐसे देखें तो, इस तरह की पहलें यह दिखाती हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल नीतियों का विषय नहीं बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है।

मुख्य बिंदु

* 19 फरवरी को पौधारोपण संकल्प के 5 वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन।
* कार्यक्रम नई दिल्ली के पूसा स्थित एपी शिंदे हॉल में होगा।
* "एक पौधा प्रतिदिन" संदेश पर आधारित अभियान।
* जनभागीदारी से अभियान को राष्ट्रीय पहचान मिली।
* पर्यावरण जागरूकता और भविष्य योजनाओं पर चर्चा होगी।
* उद्देश्य — पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना।

आगे की दिशा

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसे अभियानों में लगातार जनसहभागिता बनी रही, तो देश में हरित आवरण बढ़ाने और जलवायु संतुलन बनाए रखने की दिशा में ठोस परिणाम सामने आ सकते हैं। आने वाले समय में इस अभियान के विस्तार और प्रभाव पर सबकी नजर रहेगी।

टैलेंट अवॉर्ड सेरेमनी में 190 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया; मेधा अभियान को नेशनल लेवल पर ले जाने का ऐलान

परिवहन विशेष न्यूज

वाराणसी, 18 फरवरी, 2026: सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन एंड रिसर्च (SAR संस्थान) ने बुधवार को वाराणसी के अर्दली बाजार में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में एक टैलेंट सम्मान समारोह का आयोजन किया। यह इवेंट आर्ट ऑफ लिविंग और मुरली मित्र वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर किया गया।

प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मणिपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस-चांसलर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर प्रो. ए.पी. पांडे थे। समारोह की अध्यक्षता संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रो. एच.पी. अधिकारी ने की। खास मेहमानों में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के डीन (एकेडमिक) प्रो. वंशीधर पांडे और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज की रजिस्ट्रार डॉ. सुनीता चंद्रा शामिल थीं। इस साल, "आचार्य ब्रजवल्लभ द्विवेदी मेमोरियल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड – विरासतें बनारस सम्मान" S.B.P.G. कॉलेज, बड़गांव के प्रिंसिपल श्री उदय प्रकाश को शिक्षा के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए और INTACH वाराणसी चैप्टर के कोऑर्डिनेटर श्री अशोक कपूर को सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता में उनके योगदान के लिए दिया गया। "स्वर्गीय बदलेव प्रसाद टंडन मेमोरियल सारस्वत सम्मान" वैदिक विद्वान श्री रमन शास्त्री को दिया गया।

मेहमानों का स्वागत करते हुए, संस्था के संरक्षक, प्रो. राम सुधार सिंह ने सभा को संबोधित किया। प्रो. तरुण कुमार द्विवेदी ने आचार्य ब्रजवल्लभ द्विवेदी के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला और संस्था के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। उद्योगपति श्री राकेश टंडन ने फाउंडेशन का परिचय दिया।

अपने भाषण में, मुख्य अतिथि प्रो. ए.पी. पांडे ने कहा कि प्रतियोगिताएं छात्रों की मानसिक क्षमताओं को विकसित करने और उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करने में मदद करती हैं। उन्होंने आज के युग में AI और IQ के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और छात्रों के बौद्धिक विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए SAR संस्थान की सराहना की। खास मेहमान प्रो. वंशीधर पांडे ने स्टूडेंट्स को देश बनाने में योगदान देने और एकता और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की सलाह दी। डॉ. सुनीता चंद्रा ने स्टूडेंट्स को पढ़ाई और सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के बीच तालमेल बिठाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री के.एस. परिहार ने स्टूडेंट्स में सामाजिक ज़िम्मेदारी बढ़ाने के महत्व पर ज़ोर दिया। अपने प्रेसिडेंशियल भाषण में, प्रो. एच.पी. अधिकारी ने कहा कि शिक्षा बच्चे को बनाती है, जबकि समाज उस विकास को दिशा देता है। सहयोगी फाउंडेशन के डायरेक्टर, श्री संदीप श्रीवास्तव ने घोषणा की कि SAR संस्थान और मुरली मित्र वेलफेयर फाउंडेशन मिलकर मेधा अभियान को नेशनल लेवल तक बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के दौरान, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के ऑफिसर श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव की लिखी किताब "प्रयागराजः हिस्ट्री इन द मिरर" भी रिलीज़ की गई। इवेंट में, अलग-अलग स्कूलों के 45 स्टूडेंट्स को मौके पर ही कैश प्राइज़, गिफ्ट, शील्ड और सर्टिफिकेट मिले। इसके अलावा, 30 स्कूलों के 190 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। क्लास 5 से 10 तक के होनहार स्टूडेंट्स को टॉप अवॉर्ड दिए गए। प्रोग्राम का संचालन डॉ. राकेश्वरी प्रसाद ने किया और धन्यवाद ज्ञापन संस्था के वाइस प्रेसिडेंट और मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने दिया। समारोह में कई शिक्षाविद, समाजसेवी और जाने-माने नागरिक मौजूद थे।

अच्छा लेखन समाज के काम आना चाहिएः डॉ. रीता बहुगुणा जोशी

परिवहन विशेष न्यूज

वाराणसी: सीनियर पत्रकार और लेखक विजय विनीत की लिखी किताब "सपनों की पगडंडियां" का वाराणसी में अशोका इंस्टीट्यूट के बुद्ध ऑडिटोरियम में ऑफिशियली विमोचन किया गया। इवेंट की चीफ गेस्ट रीता बहुगुणा जोशी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि साहित्य तभी सार्थक होता है जब वह समाज में पॉजिटिव योगदान दे। उन्होंने किताब को संघर्ष, पक्के इरादे और शिक्षा के प्रति समर्पण की एक प्रेरणा देने वाली गाथा बताया।

किताब में प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की जीवन यात्रा पर रोशनी डाली गई है। डॉ. जोशी ने बताया कि वाइस-चांसलर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ एक्टिव रूप से जुड़े रहते हुए शिक्षा और क्षेत्रीय भाषाओं को नई दिशा दी।

मौजूद खास स्पीकर्स में नवभारत टाइम्स लखनऊ के एडिटर सुधीर मिश्रा; सीनियर लेखक व्योमेश शुक्ला; और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह के साथ कई और जाने-माने लोग शामिल थे। स्पीकर्स ने किताब की तारीफ की और विजय विनीत को एक सेंसिटिव और निडर पत्रकार बताया।

इवेंट का समापन मेहमानों के सम्मान के साथ हुआ। प्रोग्राम की एंकरिंग अशोक आनंद ने की, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सोनम उपाध्याय ने दिया।

बजट 2026-27 : आर्थिक समस्याएं और औंधी रणनीति, (आलेख : प्रभात पटनायक, अनुवाद : राजेंद्र शर्मा)

अब जबकि पूंजीवाद का सर्वोच्च दूत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तक भारत के जीडीपी के अनुमानों की विश्वसनीयता पर संदेह जता चुका है, ठीक-ठीक बजट के आंकड़ों का, जो जीडीपी के एक खास स्तर तथा रुपयों में जीडीपी में एक खास वृद्धि दर को मानकर चलने पर आधारित होते हैं, कोई खास अर्थ ही नहीं रह जाता है।

वास्तव में वर्तमान बजट में, करारोपण संबंधी अनेक कदमों की घोषणा करते हुए, इसके अनुमान तक देने की ज़हमत नहीं उठायी गयी है कि इन कदमों से राजस्व में कितनी कमी या बढ़ोतरी होने जा रही है। फिर भी बजट के आंकड़ों से हम इस बजट की रणनीतिक दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं और हैरानी की बात नहीं है कि यह रणनीतिक दिशा, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में, एक पूरी तरह से विकृत रणनीति है।

इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याएं इस प्रकार हैं : आर्थिक असमानता में बेतहाशा बढ़ोतरी, जिसका परिमाण पिछले सौ वर्ष के दौरान, किसी भी समय में इतना ज्यादा नहीं था; शुद्ध गरीबी में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है, जिसे शुरुआत में योजना आयोग द्वारा दैनिक कैलोरी आहार के मानक के आधार पर परिभाषित किया गया था; और बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी मार में अब देश के शिक्षित युवाओं का विशाल हिस्सा भी आ चुका है। इन समस्याओं का एक साझा समाधान यह है कि आम लोगों के हाथों में बड़े पैमाने पर क्रय शक्ति पहुंचायी जाए। लेकिन, अगर जीडीपी के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटे को नहीं बढ़ाना हो तो, इसे अमीरों की कीमत पर कर एकत्र करने के खासे बड़े प्रयास के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। इससे, उपभोग की मांग में बढ़ोतरी के रास्ते, अर्थव्यवस्था में सकल मांग का स्तर बढ़ेगा और यह उत्पाद तथा रोजगार में बढ़ोतरी की ओर और गरीबी में कमी की ओर भी ले जाएगा। इससे आय की असमानता भी घटेगी क्योंकि अमीरों की करोपरांत आय का स्तर, अन्यथा जो होता, उससे घटकर होगा।

लेकिन, बजट रणनीति की विकृति, इसमें निहित है कि उसमें जो दिशा ली जानी चाहिए थी, उससे ठीक उल्टी दिशा ली गयी है। जीडीपी के हिस्से के तौर पर कुल कर राजस्व में कोई बढ़ोतरी होने के बजाए, मामूली गिरावट ही हुई है और यह 2023-24 तथा 2024-25 के 11.5 फीसद तथा 2025-26 (संशोधित अनुमान) के 11.4 फीसद से कुछ घटकर, 2026-27 में 11.2 फीसद रह गया है। और बताया गया है कि इसके साथ ही राजकोषीय घाटा 2024-25 के 4.8 फीसद और 2025-26 (संशोधित अनुमान) के 4.4 फीसद से घटकर, 4.3 फीसद हो जाना है। इस तरह के कुल सरकारी खर्चे के दायरे में, जिसकी सीमाएं सरकार के एक ओर अमीरों पर कर बढ़ाने और दूसरी ओर राजकोषीय घाटा बढने देने, दोनों से ही इंकार ने तय कर दी हैं, पूंजी व्यय में बढ़ोतरी की गयी है और इसका हिस्सा 2024-25 के जीडीपी के 4.0 फीसद तथा 2025-26 (संशोधित अनुमान) के 3.9 फीसद से बढ़कर, 2026-27 में 4.4 फीसद हो गया है।

राज्यों पर बढ़ता हमला

बहरहाल, पूंजी व्यय में यह बढ़ोतरी भी भ्रामक ही है। केंद्र सरकार का अपना पूंजी व्यय तो, जो 2023-24 में तथा 2024-25 में जीडीपी के 3.2 फीसद के बराबर था और 2025-26 (संशोधित अनुमान) में कुछ गिरकर 3.1 फीसद रह गया था, 2026-27 में 3.1 फीसद ही बना रहने जा रहा है। बढ़ोतरी होनी है, पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ग्रांट इन एड में, जो 2024-25 के 0.8 फीसद तथा 2025-26 के संशोधित अनुमान के 0.9 फीसद से बढक़र, 2026-27 में 1.3 फीसद हो जानी है। लेकिन, इस आखिरी आइटम में मगरेगा का आवंटन भी शामिल है, जिसकी फंडिंग अब केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच, 60:40 के आधार पर साझा की जा रही होगी, जबकि पहले यह साझेदारी 90:10 के आधार पर ही हो रही थी।

इसका अर्थ यह हुआ कि अगर राज्य सरकारें, जो पहले ही फंड की कमी से जूझ रही हैं, अपना आनुपातिक हिस्सा नहीं जुटा पाती हैं, जो जुटाना उनके लिए मुश्किल होगा, उस सूरत में केंद्र को भी मूल रूप में उसके द्वारा आवंटित हिस्सा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उस सूरत में केंद्र सरकार को बजट में दर्शाया गया खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा और इसके ऊपर से वह इस कार्यक्रम की विफलता का दोष आसानी से राज्य सरकारों के सिर पर डालने में कामयाब हो जाएगी, जबकि इस योजना के व्यय के 60:40 के अनुपात में बंटवारे के फैसले में, राज्य सरकारें तो कहीं से शामिल ही नहीं थीं। यह फैसला तो इकतरफा तरीके से और पूरी तरह से मनमाने ढंग से केंद्र सरकार ने लिया था और उसे राज्यों पर तो थोप भर दिया गया था।

कथित ''सहकारी संघवाद'' की दिखावटी संज्ञा की यही हकीकत है। इसके नाम पर हो यह रहा है कि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से राज्य सरकारों के संसाधनों तथा उनकी जिम्मेदारियों को तय कर रही है और इस तथ्य का इस्तेमाल अपने चहेते राज्यों को बढ़ावा देने के लिए कर रही है, जो इसके पक्षपाती होने के चलते जाहिर है कि भाजपा-शासित राज्यों के साथ पक्षपात के रूप में सामने आता है, जबकि गैर-भाजपा सरकारों के हाथ बांधे जाते हैं और फिर इन विपक्षी सरकारों पर कथित 'खराब प्रदर्शन' का दोष डाला जाता है।

वाइवी रेड्डी की अध्यक्षता में, 14वें वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की थी कि करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा, 2020 तक पहले के 32 फीसद से बढ़ाकर 42 फीसद कर दिया जाए। लेकिन, केंद्र सरकार ने बाकायदा कर लगाने के बजाए, जिनकी प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझा करना होता है, सैस तथा सरचार्ज लगाने का ही सहारा लिया, जिनकी प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझा नहीं करना होता है और इस तरह उसने यह सुनिश्चित किया कि सैस तथा सरचार्ज समेत कुल कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा, 34 फीसद से ज्यादा ही ही नहीं पाए। यह व्यावहारिक रूप से केंद्र के हाथों में संसाधनों के केंद्रीयकरण की ही एक अवैधतिकड़म है।

पूंजी व्यय में बढ़ोतरी भ्रामक

इस कपट लीला के बावजूद, केंद्र सरकार का व्यय जहां का तहां ही रहने जा रहा है (अगर जैसी कि हमने पीछे चर्चा की, पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता बजटीय प्रावधान से घटकर रहती है) या फिर जीडीपी के हिस्से के तौर पर उसमें मामूली सी बढ़ोतरी ही होने जा रही है। लेकिन, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के उन तीन फौरी संकटों पर काबू पाना संभव ही नहीं है, जिनकी हम शुरू में ही चर्चा कर आए हैं। वास्तव में समग्रता में केंद्र द्वारा पूंजी व्यय, जनता के हाथों में हस्तांतरणों के मुकाबले कम रोजगार पैदा करने वाला होता है। इसकी वजह यह है कि ढांचागत खर्च का मजदूरी का घटक, जो कि पूंजी व्यय के केंद्र में होता है, कुल पूंजी व्यय का एक अंश भर होता है। इसके विपरीत, जनता के लिए हस्तांतरित समूची राशि ही, व्यावहारिक मानों में एक प्रकार से मजदूरी के भुगतान का काम करती है। और जाहिर है कि अगर ढांचागत निवेश के लिए रखे गए संसाधनों को स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को लगाने आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन संस्थाओं में स्टाफ की भारी कमी है, या फिर इन संसाधनों का उपयोग सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उस सूरत में इस निवेश का रोजगार पर प्रत्यक्ष असर और इन नये रोजगार पाने वाले लोगों द्वारा पैदा की जा रही मांग के चलते द्वितीयक बहुगुणनकारी प्रभाव, कहीं ज्यादा उल्लेखनीय होगा।

इसलिए, न सिर्फ यह कि यह बजट बेरोजगारी तथा गरीबी में बढ़ोतरी के रुझान को पलटने के लिए कुछ भी नहीं करता है, वास्तव में वह इससे उल्टा काम ही करता है। यह किया जाता है एक ओर तो निजी क्षेत्र को (और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों को भी) कर रियायतें देने के जरिए और दूसरी ओर प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने करने वाले खर्चों तथा जनता के पक्ष में हस्तांतरणों की कीमत पर, ढांचागत व्यय का अनुपात बढ़ाने के जरिए।

ऐसा लगता है कि सरकार को इस सचाई का पता ही नहीं है कि निजी निवेश, बढ़ती मांग के प्रत्युत्तर में ही आता है। चाहे कितनी ही कर रियायतें क्यों न दी जाएं, पूंजीपतियों को निवेश बढ़ाने के लिए तब तक प्रेरित नहीं किया जा सकता है, जब तक पहले ही स्थापित उत्पादन क्षमता ठाली पड़ी रहती है। प्रसंगतः बता दें कि यही वजह है कि इससे पहले दी गयी तमाम कर रियायतों के बावजूद, जिनमें 2019 में कारपोरेट करों में कटौती करने जैसी भारी रियायतें भी शामिल थीं, निजी निवेश सुस्त ही बना रहा है। इसी तरह, एक ऐसे दौर में जब आम तौर पर विश्व अर्थव्यवस्था में तथा इसलिए निवेश में भी सुस्ती बनी हुई है, यह उम्मीद करना कि बहुराष्ट्रीय निगमों के करों के घटाए जाने भर से भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह चले आएंगे, बेतुकी बात है। और इसकी उम्मीद तब करना जब ट्रंप अमेरिका से निवेशों को बाहर जाने से रोकने के लिए टैरिफ बढ़ाने के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, और भी बेतुका है।

हालात बदतर होंगे

दो और कारणों से हालात और भी बदतर होने जा रहे हैं। पहला तो यह 2027 में प्रतिव्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरण की योजना खत्म होने वाली है। यह ग्रामीण भारत के लिए जीवन रेखा बनी रही है और इसका अंत होने से लोगों की बदहाली बहुत बढ़ जाएगी। दूसरा कारण है, व्यापार समझौते जिन पर दस्तखत किए जा रहे हैं और इनमें अब अमेरिका के साथ हुआ व्यापार समझौता भी शामिल है। अगर खबरों का सच माना जाए तो यह बाद वाला समझौता अमेरिका को तो भारतीय मालों पर 18 फीसद टैरिफ लगाने की इजाजत देता है, जबकि भारत को अमेरिकी मालों के शुल्क मुक्त आयात के लिए बाध्य करता है। इस तरह की 'नाबराबरी की संधि' भारतीय कृषि और खासतौर पर डेयरी क्षेत्र में भारी तकलीफें पैदा करने जा रही है। लेकिन, फासीवादी सरकार की तो जनता के प्रति दायलुता की अपनी छवि बनाने में ही ज्यादा दिलचस्पी है, न कि वास्तव में जनता की जीवन-दशाओं को बेहतर बनाने में।

1930 के दशक के फासीवाद और वर्तमान फासीवादी सरकारों के बीच के अंतर को, यह बजट रेखांकित करता है। 1930 के दशक में फासीवादी देशों में सैन्य खर्चों को बढ़ाने के लिए, राजकोषीय घाटे में भारी बढ़ोतरियां की गयी थीं। इससे सकल मांग का स्तर पर बहुत बढ़ा था और ये देश महामंदी से उबरने में कामयाब हो गए थे। इसके अलावा सरकारी खर्चों में यह बढ़ोतरी, ऑटोबानों के निर्माण तथा सैन्य साज-सामान की खरीद जैसे ढांचागत निवेश तक ही सीमित नहीं थे बल्कि इनमें सैन्य बलों के आकार में बढ़ोतरी भी शामिल थी, जिससे प्रत्यक्ष तरीके से रोजगार बढ़ा था। लेकिन, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जैसी आज की फासीवादी सरकारें, न तो सकल मांग को बढ़ाने के लिए राजकोषीय घाटा बढ़ा सकती हैं और न उसमें इसका बूता है कि (सिर्फ ढांचागत क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने से भिन्न) जनता के लिए प्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ा सकें या उसके पक्ष में हस्तांतरण कर सकें। जहां तक रोजगार बढ़ाने का सवाल है, वे दोनों ही पहलुओं से नाकाम हैं। इसलिए, आने वाले महीनों में उनका ''नफरत फैलाने'' का सहारा लेना और भी बढ़ जाने वाला है।

(लेखक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफ़ेसर एमेरिटस हैं।

आखिर जातीय, धार्मिक व क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने वाली लोकतांत्रिक प्रवृत्ति पर कैसे पाएंगे काबू?

कमलेश पांडेय

दुनिया को 'वसुधैव कुटुम्बकम' का संदेश देने वाला जनतांत्रिक भारत आज जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने वाली 'ब्रितानी' व 'भुगलिया' सियासत के चक्रव्यूह में फंसा पड़ा है। इससे 'सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया' जैसी उसकी उदात्त सोच भी कठघरे में खड़ी प्रतीत हो रही है। यहां की प्रतिभाशाली और प्रभुत्ववाली सामान्य जातियों (सवर्णों) के खिलाफ देश में जो लक्षित पूर्वाग्रही राजनीति कथित दलित-ओबीसी नेताओं के द्वारा की जा रही है, उससे देश व समाज के सामने विभिन्न नैतिक व वैधानिक सवाल उठ खड़े हुए हैं!

हैरत की बात है कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की जगह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के नारे लगाए जाते हैं। कहीं जाति, कहीं धर्म और कहीं भाषा-क्षेत्र के नाम पर लोगों के उत्पीड़न हो रहे हैं। वहीं कहीं सामाजिक न्याय आधारित आरक्षण और साम्प्रदायिक सोच आधारित अल्पसंख्यकवाद के अव्यवहारिक पहलुओं को हवा देकर आमलोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। आलम यह है कि ऐसे करने वाले नेता, उनके हमकदम मस्त हैं जबकि आमलोग त्रस्त हैं।

हद तो यह कि हमारे संविधान के संरक्षक अनर्गल दलीलें देकर मानवता का गला घोंट रहे हैं जबकि यही प्रवृत्ति कतिपय संविधान निर्माताओं में भी दिखी थी। वहीं आज के कथित रखवाले जन्मांध 'धृतराष्ट्र' की भूमिका निभा रहे हैं। इनके जैसे ही नेताओं की खामोशी से जहां 1947 में साम्प्रदायिक विभाजन हुआ, वहीं इनके षडयंत्र से आजादी के बाद से ही जातीय, क्षेत्रीय व नवसंप्रदायिक विभाजन की प्रवृत्ति हावी होती दिख रही है, जो आज भी जारी है। ऐसे में एक और महाभारत छिड़ना तय है। युनः विभाजन होना तय है। इतिहास साक्षी है कि जब कभी भी महाभारत होता है तो संख्याबल पर बुद्धिबल ही भारी पड़ती है और आगे भी यही होगा।

कहना न होगा कि कोई भी लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता व बन्धुत्व की बुनियाद पर मजबूत होता है, लेकिन जब बहुमत की सियासी शरारत शुरू हो जाए और वामपंथियों के वर्गवादी राजनीति को मात देने के लिए पूंजीवादी प्रभाव वश जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की सियासत तेज हो जाए तो देर सबेर राष्ट्र राज्य का बिखरना तय होता है। इसलिए इनसे जुड़े राजनीतिक स्थकंडों और उन्हें शह देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को यदि समय रहते ही नहीं बदला गया तो बाद में इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होगा! ऐसा इसलिए कि जातिवादी कैंसर, सांप्रदायिक एड्स और क्षेत्रवादी तपेदिक (टीबी) से शांतिप्रिय व सहनशील भारतीय समाज सदियों से ग्रसित है लेकिन बीती सदी में इन्हें एक कानूनी स्वरूप देकर स्थिति को जटिल चुनौती बना दी गई है। किसी समूह के इतिहास को साक्षी मानकर उनके वर्तमान को रौंदने की जो सियासी प्रवृत्ति भारत में हावी है, उससे सामान्य व कथित सवर्ण जातियों में भारी रोष व्याप्त है।

इसलिए समावेशी संवैधानिक प्रावधानों, हिंसा-प्रतिहिंसा पर समान कानूनी सख्ती और सामाजिक जागरूकता के संयोजन से ही अब इस जटिल स्थिति से निबटना संभव है, लेकिन हमारी सियासी सोच इसके विपरीत है। वह आज भी विदेशी फूट डालो, शासन करो पर केंद्रित है। लिहाजा, कतिपय कानूनी उपाय अपेक्षित हैं। पहले चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों और नेताओं के भाषणों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए, तथा IPC की धारा 153A (समूहों के बीच शत्रुता फैलाना), 295A (धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाना) और प्रतिनिधित्व ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123(3) के तहत तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाकर, जैसे नफरत भरी भाषा पर त्वरित गिरफ्तारी और पार्टी मान्यता रद्द करने का प्रावधान जोड़ना, ऐसे स्थकंडों पर अंकुश लग सकता है।

लगे हाथ संस्थागत सुधार के लिए भी समवेत कदम उठाने होंगे। खासकर राजनीतिक दलों को टिकट वितरण और मंत्रिमंडल गठन में जाति-धर्म आधारित समीकरणों से ऊपर उठना होगा, जबकि चुनाव सुधारों के जरिए आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने वाले एआई-जनरेटेड कंटेंट और प्रचार पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए, जैसा कि हालिया चुनावी दौर में देखा गया।

वहीं, सामाजिक व शैक्षिक प्रयास से भी इस स्थिति से निबटा जा सकता है। विशेषकर शिक्षा प्रणाली में समावेशी पाठ्यक्रम लागू कर नई पीढ़ी को जाति-धर्म से ऊपर उठने की प्रेरणा दी जाए, तथा धर्मगुरुओं और सामाजिक नेताओं पर निगरानी रखी जाए। मतदाताओं को जागरूक अभियान चलाकर वोटिंग में योग्यता और नीतियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि विभाजनकारी रणनीतियां अप्रभावी हो जाएं।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी दो टूक शब्दों में कहा है कि राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाने का काम करना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाने का काम करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि गाइडलाइन बनने पर भी उनका पालन कौन करेगा क्योंकि भाषण विचारों से उत्पन्न होते हैं और इन्हें नियंत्रित करना कठिन है। कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, साथ ही राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी पर भी इशारा किया।

जस्टिस बागची ने कहा कि हेट स्पीच पर पहले से सिद्धांत बने हैं, लेकिन आदेश लागू करना चुनौतीपूर्ण है। कोर्ट ने जहरीले सामाजिक माहौल की चिंता स्वीकारी, लेकिन चुनिंदा नेताओं को टारगेट करने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की नसीहत दी। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने नेताओं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के भाषणों को हेट स्पीच से रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने की मांग की थी। याचिका में दो प्रमुख दिशानिर्देश मांगे गए थे। पहला, संवैधानिक पदों या सार्वजनिक कार्यालयों पर बैठे लोगों के भाषण संवैधानिक नैतिकता के अधीन हों और दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। दूसरा, इन पदधारकों के सार्वजनिक भाषणों को नियंत्रित करने के लिए बिना पूर्व सेंसरशिप के दिशानिर्देश जारी किए जाएं ताकि संवैधानिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित हो।

उल्लेखनीय है कि यह जनहित याचिका 12 पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों और सिविल सोसायटी सदस्यों द्वारा दायर की गई थी। इसमें असम सीएम हिमंत बिस्व सरमा, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के कथित नफरती बयानों का हवाला दिया गया। हालांकि कोर्ट ने इसे पक्षपाती मानते हुए नई व्यापक याचिका दायर करने को कहा जिसमें अन्य नेताओं की टिप्पणियों का भी उल्लेख हो।

बता दें कि गत 16 फरवरी 2026 को चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने रूप रेखा वर्मा समेत 12 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार किया जिसमें नेताओं और मीडिया के लिए हेट स्पीच व भाषणों पर दिशानिर्देश बनाने की मांग थी, खासकर असम सीएम हिमंत बिस्व सरमा के कथित बयानों के संदर्भ में लेकिन कोर्ट ने मौजूदा याचिका पर सुनवाई से इनकार कर नई याचिका दायर करने को कहा।

विवाह के पंडाल में किताबों की प्रदर्शनी: एक नई और सराहनीय पहल

● डॉ. विजय गर्ग

विवाह में आए मेहमान अक्सर खाली समय में बातचीत या मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। यदि पंडाल में किताबों का एक आकर्षक कोना सजाया जाए तो अतिथि साहित्य, प्रेरक पुस्तकों, बच्चों की कहानियों, आध्यात्मिक ग्रंथों या प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों को देख सकते हैं। इससे समारोह में सार्थक सहभागिता बढ़ती है।

भारतीय विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि संस्कृतियों, परिवारों और मूल्यों का उत्सव होता है। बदलते समय के साथ विवाह समारोहों में नई-नई परंपराएँ जुड़ रही हैं। इसी क्रम में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक पहल उभरकर सामने आई है—विवाह के पंडाल में किताबों की प्रदर्शनी। यह नई रिवाज़ न केवल समारोह को अलग पहचान देती है, बल्कि समाज में ज्ञान और पढ़ने की संस्कृति को भी बढ़ावा देती है।

परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम

पहले विवाह समारोहों में सजावट, संगीत और भोजन मुख्य आकर्षण होते थे। आज शिक्षित और जागरूक परिवार विवाह को एक सामाजिक संदेश देने का अवसर मान रहे हैं। पुस्तक प्रदर्शनी इस सोच का प्रतीक है—जहाँ उत्सव के साथ ज्ञान का प्रसार भी होता है।

मेहमानों के लिए अनोखा अनुभव

विवाह में आए मेहमान अक्सर खाली समय में बातचीत या मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। यदि पंडाल में किताबों का एक आकर्षक कोना सजाया जाए तो अतिथि साहित्य, प्रेरक पुस्तकों, बच्चों की कहानियों, आध्यात्मिक ग्रंथों या प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों को देख सकते हैं। इससे समारोह में सार्थक सहभागिता बढ़ती है।

उपहार देने की संस्कृति में सकारात्मक बदलाव

कई परिवार नकद या सजावटी वस्तुओं की बजाय मेहमानों को पुस्तकें भेंट करने लगे हैं। यह परंपरा "ज्ञान का उपहार" देने की प्रेरणा देती है। एक अच्छी पुस्तक जीवन भर साथ रहती है और पाठक के विचारों को समृद्ध करती है।

बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा

विवाह समारोह में पुस्तक प्रदर्शनी बच्चों और युवाओं को पढ़ने की ओर आकर्षित करती है। रंगीन चित्र पुस्तकों से लेकर विज्ञान, जीवन कौशल और व्यक्तित्व विकास की किताबें उन्हें नई दिशा दे सकती हैं।

सामाजिक संदेश: ज्ञान ही सच्ची संपत्ति

ऐसी पहल समाज को यह संदेश देती है कि वैभव और दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान और संस्कार। यह रिवाज़ पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देकर समाज को जागरूक और शिक्षित बनाने में योगदान दे सकती है।

कैसे करें आयोजन?

एक अलग पुस्तक कोना या स्टॉल तैयार करें

विभिन्न आयु वर्ग के लिए किताबें रखें

स्थानीय लेखकों की पुस्तकों को शामिल करें

मेहमानों के लिए "एक किताब साथ ले जाएँ" व्यवस्था करें

अपनी पसंद और विचारधारा को प्रदर्शित करने का एक मंच भी बन गई हैं। जहाँ पहले शादियों में केवल भव्य सजावट, डीजे और पकवानों की चर्चा होती थी, वहीं अब 'किताबों की प्रदर्शनी' जैसा एक अनूठा रिवाज अपनी जगह बना रहा है। यह बदलाव समाज की बदलती सोच और बौद्धिक विकास का परिचायक है।

इस रिवाज की शुरुआत क्यों?

आज की युवा पीढ़ी 'दिखावे' से ऊपर उठकर कुछ 'सार्थक' करने की ओर अग्रसर है। विवाह में किताबों की प्रदर्शनी लगाने के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

बौद्धिक उपहार: लोग अब प्लास्टिक या शो-पीस के बजाय ज्ञान बाँटने में विश्वास रख रहे हैं।

सार्थक स्वागत: मेहमानों के लिए खाने-पीने के साथ-साथ फुर्सत के पलों में अच्छी किताबें पढ़ना एक नया और सुखद अनुभव होता है।

प्रेरणा का स्रोत: नई पीढ़ी और बच्चों को डिजिटल दुनिया से हटाकर कागजों की महक और पढ़ने की संस्कृति से जोड़ना।

कैसे बदल रही है यह परंपरा?

इस नए रिवाज को अलग-अलग तरीकों से अपनाया जा रहा है:

1. दिखावे से ऊपर 'बौद्धिक विकास'

शादियाँ अक्सर केवल दिखावे का जरिया बन जाती हैं। पंडाल में किताबों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि परिवार संस्कार और ज्ञान को भौतिक संपदा से ऊपर रखता है। यह मेहमानों को एक नई चर्चा का विषय देता है—खाने के स्वाद के अलावा किताबों के विषय पर भी बात हो सकती है।

2. 'रिटर्न गिफ्ट' के रूप में किताबें

अक्सर शादियों में हम मिठाई के डिब्बे या प्लास्टिक के सामान उपहार में देते हैं। इसकी जगह यदि प्रदर्शनी से मेहमान अपनी पसंद की किताब चुनकर घर ले जा सकें, तो यह उनके जीवन पर स्थायी प्रभाव छोड़ेगा। एक अच्छी किताब किसी के विचार बदल सकती है।

3. बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा

शादी में आए बच्चे और युवा अक्सर शोर-शराबे से ऊब जाते हैं। एक कोना जहाँ रंग-बिरंगी किताबें, कॉमिक्स या प्रेरणादायक कहानियाँ हों, उन्हें मोबाइल स्क्रीन से दूर कर पढ़ने की आदत की ओर मोड़ सकता है।

4. सांस्कृतिक विरासत का संगम

विवाह दो परिवारों और संस्कृतियों का मिलन है। प्रदर्शनी में अगर:

साहित्य और इतिहास की किताबें हों।

स्थानीय लेखकों की रचनाएँ हों।

पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों पर आधारित पुस्तकें हों।

...तो यह उत्सव की गरिमा को कई गुना बढ़ा देता है।

पढ़ने के महत्व पर संदेश बोर्ड लगाएँ

निष्कर्ष

विवाह के पंडाल में किताबों की प्रदशानी एक छोटी पहल होते हुए भी बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत है। यह परंपरा उत्सव को ज्ञान से जोड़ती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यदि यह नई रिवाज़ व्यापक रूप से अपनाई जाए, तो विवाह समारोह केवल आनंद का अवसर नहीं, बल्कि ज्ञान-वितरण का उत्सव भी बन सकते हैं।

विवाह में रोशनी के साथ यदि ज्ञान की ज्योति भी जले, तो समाज का भविष्य और उज्ज्वल हो सकता है।

अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका

डॉ. विजय गर्ग

ऐसे युग में जहां सूचनाएं अंतहीन रूप से प्रवाहित होती हैं और ध्यान भटकाने वाली चीजें केवल एक क्लिक की दूरी पर होती हैं, एक तेज और चुस्त दिमाग बनाए रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। शरीर की मांसपेशियों की तरह, मस्तिष्क को भी सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए नियमित व्यायाम, उचित पोषण और स्वस्थ आदतों की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना केवल तथ्यों को याद करने के बारे में नहीं है; इसमें ध्यान, रचनात्मकता, भावनात्मक संतुलन और समस्या-समाधान क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है।

आजीवन शिक्षा में संलग्न रहें

नए कौशल सीखने से तंत्रिका संबंध उत्तेजित होते हैं और मस्तिष्क लचीला रहता है। किताबें पढ़ना, नई भाषा सीखना, विज्ञान का अध्ययन करना या इतिहास की खोज करना स्मृति और समझ को मजबूत करता है। पहेलियाँ सुलझाना, शतरंज खेलना या रणनीति खेलों में भाग लेना जैसी गतिविधियां तर्क कौशल और संज्ञानात्मक चपलता को बढ़ाती हैं।

माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें

माइंडफुलनेस अभ्यास से ध्यान, भावनात्मक स्थिरता और विचार की स्पष्टता में सुधार होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अध्ययनों सहित शोध से पता चलता है कि ध्यान ध्यान अवधि में सुधार कर सकता है और तनाव को कम कर सकता है। प्रतिदिन 10 मिनट भी शांत चिंतन या गहरी सांस लेने से मन शांत हो सकता है और एकाग्रता बढ़ सकती है।

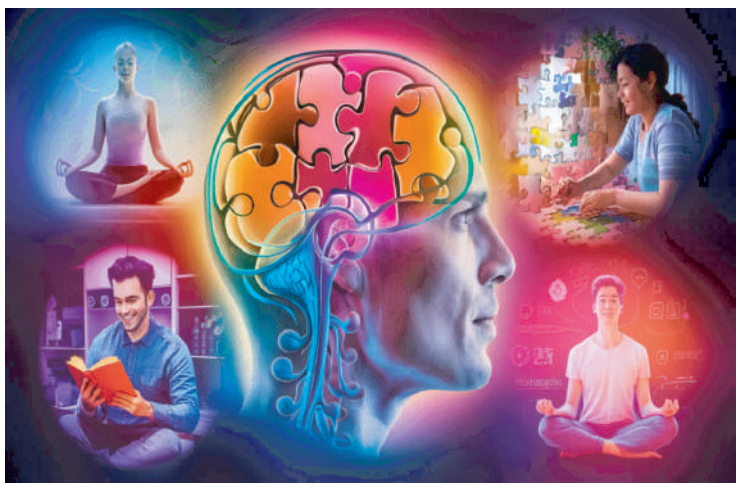

मस्तिष्क शक्ति के लिए व्यायाम

शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है और नई मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास में सहायता करती है। पैदल चलना, योग, साइकिल चलाना या स्ट्रेंचिंग व्यायाम मूड और संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाते हैं। नियमित गतिविधि से तनाव हार्मोन भी कम हो जाता है, जो स्मृति और सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

स्वस्थ भोजन से मस्तिष्क को पोषण दें

संतुलित आहार मस्तिष्क स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड (जैसे अखरोट और अलसी), एंटीऑक्सीडेंट (फल और सब्जियां) और साबुत अनाज से भरपूर खाद्य पदार्थ स्मृति और एकाग्रता को बढ़ावा देते हैं। हाइड्रेटेड रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्जलीकरण से ध्यान केंद्रित करने और मानसिक स्पष्टता में कमी आ सकती है।

नींद: मस्तिष्क की मांसपेशियों को रीसेट करने वाला बटन

गुणवत्ता वाली नींद स्मृति समेकन और मानसिक सुधार के लिए आवश्यक है। नींद के दौरान, मस्तिष्क सूचना को संसाधित करता है और सीखने के मार्गों को मजबूत बनाता है। वयस्कों और छात्रों दोनों को एक समान नींद की दिनचर्या बनाए रखने से लाभ मिलता है।

डिजिटल ओवरलोड को सीमित करें

लगातार सूचनाएं और अत्यधिक स्क्रीन समय ध्यान को बाधित करता है और उत्पादकता को कम करता है। डिवाइस के उपयोग के लिए निर्धारित समय निर्धारित करने और नियमित ब्रेक लेने से मानसिक ध्यान बहाल करने में मदद मिलती है और संज्ञानात्मक दक्षता में सुधार होता है।

सामाजिक संपर्क और भावनात्मक स्वास्थ्य

बातचीत, टीमवर्क और सार्थक रिश्ते सोचने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक जुड़ाव मस्तिष्क को भावनाओं की व्याख्या करने, उचित प्रतिक्रिया देने और सहानुभूति बनाने के लिए चुनौती देता है।

रचनात्मकता विकसित करें

चित्रकारी, लेखन, संगीत या शिल्पकला जैसी रचनात्मक गतिविधियाँ कल्पना और नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं। रचनात्मकता मस्तिष्क को नए संबंध बनाने और समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

निष्कर्ष

मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना एक आजीवन यात्रा है जो सीखने, जागरूकता, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और रचनात्मक अन्वेषण को जोड़ती है। सरल दैनिक आदतों को अपनाने से - पढ़ना, व्यायाम करना, ध्यान करना, अच्छा खाना और सामाजिक रूप से जुड़े रहना - हम मानसिक स्पष्टता, लचीलापन और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित मस्तिष्क न केवल शैक्षणिक या व्यावसायिक सफलता में सुधार करता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी समृद्ध बनाता है, जिससे हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ अनुकूलन कर सकते हैं, और सार्थक ढंग से रह सकते हैं।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल एजुकेशनल कॉलमिस्ट एमिनेंट एजुकेशनिस्ट स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलौट पंजाब

सवालों में उलझी गुमशुदगी की गुत्थी

डॉ विजय गर्ग

समाज में किसी व्यक्ति की गुमशुदगी केवल एक घटना नहीं होती, बल्कि यह परिवार, समुदाय और प्रशासन—तीनों के लिए गहरी चिंता और असंख्य सवालों का कारण बन जाती है। जब कोई अचानक लापता होता है, तो पीछे रह जाते हैं अनुत्तरित प्रश्न, अनिश्चितता की पीड़ा और न्याय की प्रतीक्षा।

गुमशुदगी: एक बढ़ती सामाजिक चिंता

देश के विभिन्न हिस्सों में हर वर्ष हजारों लोग लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होती है। इनमें बच्चे, महिलाएँ, बुज़ुर्ग और युवा सभी शामिल होते हैं। कई मामलों में लोग घर से स्वेच्छा से निकल जाते हैं, तो कुछ मामलों में मानव तस्करी, पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव या अपराध जैसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं।

परिवार की पीड़ा और प्रतीक्षा

किसी प्रियजन के अचानक गायब हो जाने से परिवार मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संकट में घिर जाता है।

हर दस्तक पर उम्मीद जागती है।

हर फोन कॉल दिल की धड़कन बढ़ा देता है।

समय के साथ उम्मीद और निराशा का संघर्ष गहरा होता जाता है।

यह अनिश्चित प्रतीक्षा सबसे बड़ी यातना बन जाती है।

जांच प्रक्रिया और चुनौतियाँ

पुलिस और जांच एजेंसियाँ गुमशुदगी के मामलों को सुलझाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करती हैं:

सीसीटीवी फुटेज की जांच

मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग

सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण

स्थानीय नेटवर्क और मुखबिरों की सहायता

फिर भी कई मामलों में पहचान, समय की देरी, सीमित संसाधन और झूठी सूचनाएँ जांच को जटिल बना देती हैं।

डिजिटल युग: मदद भी, चुनौती भी

तकनीक ने खोज प्रक्रिया को आसान बनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें और जानकारी तेजी से फैलती हैं, जिससे लोगों को खोजने में सहायता मिलती है। दूसरी ओर, गलत जानकारी और अफवाहें जांच को भटका सकती हैं।

रोकथाम: जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता

गुमशुदगी की घटनाओं को कम करने के लिए समाज को सक्रिय भूमिका निभानी होगी:

बच्चों को सुरक्षा के बारे में जागरूक करना

बुज़ुर्गों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों पर ध्यान देना

संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देना

समुदाय स्तर पर निगरानी और सहयोग बढ़ाना

सवाल जो अब भी बाकी हैं

हर अनसुलझी गुमशुदगी कई प्रश्न छोड़ जाती है:

क्या वह स्वेच्छा से गया था या किसी साजिश का शिकार हुआ?

क्या समय पर मदद मिल सकती थी?

क्या समाज और प्रशासन और अधिक सतर्क हो सकते थे?

निष्कर्ष

गुमशुदगी की गुत्थी केवल एक कानूनी या प्रशासनिक मामला नहीं है; यह मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का विषय है। जब तक हर लापता व्यक्ति अपने घर नहीं लौटता, तब तक सवाल बने रहेंगे और समाज की जिम्मेदारी भी।

समाधान केवल जांच में नहीं, बल्कि जागरूकता, संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयास में छिपा है।

संपादकीय

चिंतन-मनन

मीठे पानी का संकट: कमी नहीं, कुप्रबंधन

(दुनिया आज मीठे जल की उपलब्धता और पहुँच—दोनों से जूझ रही है। मीठे जल की कमी से अधिक, उसकी पहुँच क्यों आज वैश्विक संकट है?)

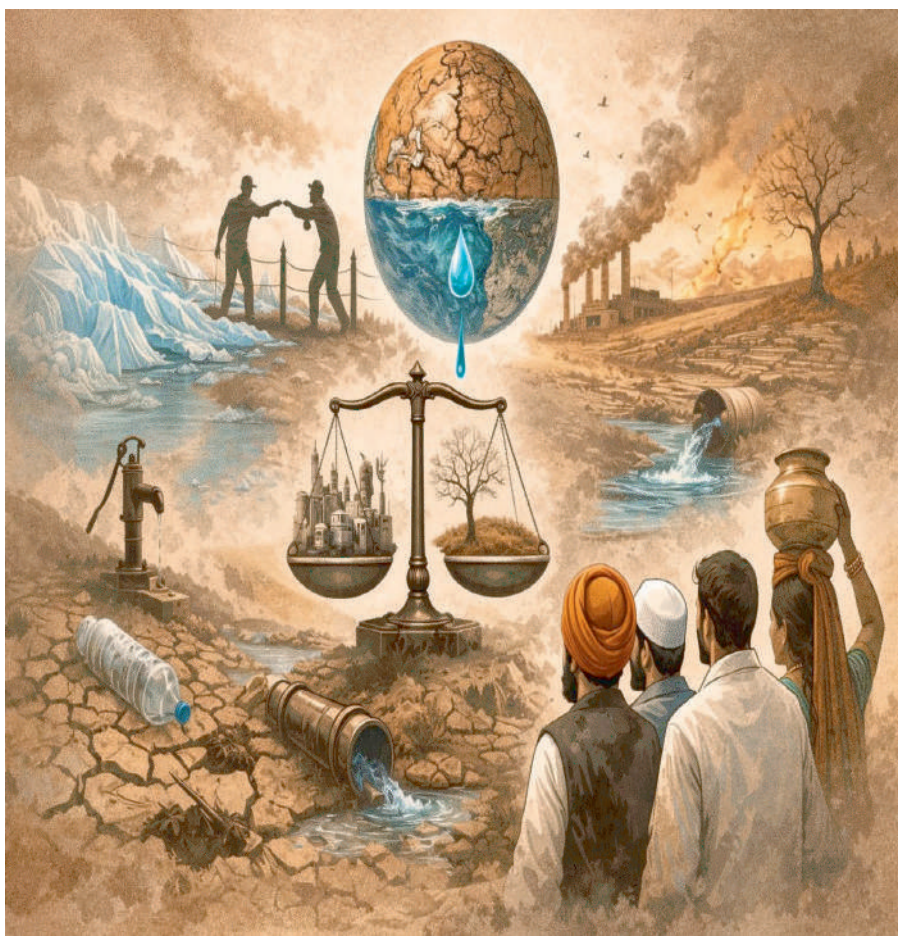

डॉ. प्रियंका सौरभ

वैश्विक मीठे जल संकट: उपलब्धता और पहुँच की दोहरी चुनौती

आज विश्व जिस सबसे गंभीर संसाधन संकट का सामना कर रहा है, उनमें मीठे जल का संकट अत्यंत गहन और बहुआयामी है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97 प्रतिशत खारा है और केवल लगभग 3 प्रतिशत मीठा जल है, जिसमें से भी बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए सुलभ है। इसके बावजूद, आज विश्व की 2–3 अरब आबादी वर्ष के किसी न किसी समय जल संकट से जूझती है। यह संकट केवल जल की भौतिक कमी का नहीं, बल्कि जल की घटती उपलब्धता और समान व सुरक्षित पहुँच—दोनों का संयुक्त संकट है, जो पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों को एक साथ प्रभावित करता है।

पिछले कुछ दशकों में मीठे जल की उपलब्धता में निरंतर गिरावट देखी गई है। इसका एक प्रमुख कारण भूजल का अत्यधिक दोहन है। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग की बढ़ती माँग ने जलभृतों पर असहनीय दबाव डाला है। हरित क्रांति के बाद सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और बोरवेल पर बढ़ती निर्भरता ने प्राकृतिक पुनर्भरण की क्षमता को पीछे छोड़ दिया है। भारत, चीन और अमेरिका जैसे देशों में भूजल स्तर का तीव्र पतन भविष्य की जल सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। कई क्षेत्रों में जलभृत स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जल उपलब्धता और भी अनिश्चित हो गई है।

जल स्रोतों का प्रदूषण मीठे जल संकट का दूसरा बड़ा कारण है। नदियों, झीलों और भूजल में बिना शोधन के छोड़ा गया घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, भारी धातुएँ और कृषि रसायन जल को अनुपयोगी बना रहे हैं। विकासशील देशों में यह समस्या और भी गंभीर है, जहाँ शोधन अवसंरचना का अभाव है। परिणामस्वरूप, कई स्थानों पर जल उपलब्ध होते हुए भी पीने योग्य नहीं रह जाता, जिससे स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है और जल की प्रभावी उपलब्धता घट जाती है।

जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिमनदों का तीव्र पिघलना, वर्षा के पैटर्न में अनिश्चितता और सूखे-बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति देखी जा रही है। हिमालय, आल्प्स और एंडीज़ जैसे क्षेत्रों में हिमनदों का सिकुड़ना दीर्घकाल में नदियों के प्रवाह को अस्थिर कर रहा है। अल्पकाल में यह बाढ़ का कारण बनता है, जबकि दीर्घकाल में स्थायी जल संकट को जन्म देता है। मानसूनी क्षेत्रों में अनियमित वर्षा ने जल भंडारण और कृषि योजना को भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

इसके साथ ही, आर्द्रभूमियों और प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रों का तेजी से क्षरण हुआ है। शहरीकरण, अवैज्ञानिक भूमि उपयोग और रियल एस्टेट विकास ने झीलों, तालाबों, बाढ़ मैदानों और दलदलों को नष्ट कर दिया है। ये पारिस्थितिक तंत्र न केवल जल संग्रह और भूजल पुनर्भरण में सहायक होते हैं, बल्कि बाढ़ और सूखे के प्रभावों को भी संतुलित करते हैं। इनके विनाश से जल चक्र का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है।

जनसंख्या वृद्धि और उपभोग के बदलते पैटर्न ने भी मीठे जल पर दबाव बढ़ाया है। शहरी जीवनशैली, जल-गहन उद्योग और भोजन की बदलती आदतें—विशेषकर मांसाहारी आहार—ने प्रति व्यक्ति जल पदचिह्न को बढ़ाया है। परिणामस्वरूप, जल की माँग प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमता से कहीं अधिक हो गई है।

जहाँ एक ओर जल की उपलब्धता घट रही है, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में जल उपलब्ध होते हुए भी लोगों की पहुँच उससे वंचित है। इसका प्रमुख कारण अपर्याप्त अवसंरचना है। कई देशों में जल संग्रहण, शोधन और वितरण की व्यवस्थाएँ कमजोर हैं। पुराने पाइपलाइन नेटवर्क, उच्च लीकेज और अपर्याप्त भंडारण के कारण बड़ी मात्रा में जल उपभोक्ताओं तक पहुँचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार विकासशील देशों में शहरी जल का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा वितरण के दौरान ही नष्ट हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, जल गुणवत्ता की समस्या भी पहुँच को सीमित करती है। जहाँ जल भौतिक रूप से उपलब्ध है, वहाँ भी प्रदूषण के कारण वह पीने योग्य नहीं रहता। दूषित जल से होने वाली बीमारियाँ आज भी कई देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की बड़ी चुनौती हैं, जिससे गरीब और हाशियाकृत समुदाय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

राजनीतिक और कानूनी बाधाएँ भी जल तक पहुँच को सीमित करती हैं। जल एक साझा संसाधन है, जिसके कारण अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय विवाद उत्पन्न होते हैं। नदियों के बँटवारे, संघीय ढाँचे में अधिकारों के टकराव और अंतरराष्ट्रीय नदी समझौतों की जटिलताओं के कारण कई बार जल-समृद्ध क्षेत्रों में भी समान पहुँच संभव नहीं हो पाती।

सामाजिक असमानता इस संकट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जल संकट का सबसे बड़ा बोझ समाज के कमजोर वर्गों—ग्रामीण गरीबों, शहरी झुग्गी बस्तियों, महिलाओं और बच्चों—पर पड़ता है। कई स्थानों पर सामाजिक भेदभाव, गरीबी और वहन क्षमता की कमी के कारण सुरक्षित जल तक समान पहुँच नहीं मिल पाती, जिससे असमानता और गहरी हो जाती है।

कमजोर जल शासन भी समस्या को जटिल बनाता है। जल प्रबंधन से जुड़ी संस्थाओं में समन्वय की कमी, विश्वसनीय डेटा का अभाव और अल्पकालिक नीतियाँ दीर्घकालिक समाधान के मार्ग में बाधा बनती हैं। कई देशों में जल से जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियाँ अनेक मंत्रालयों और एजेंसियों में बँटी होती हैं, जिससे एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाता।

मौसमी असंतुलन भी जल पहुँच की समस्या को बढ़ाता है। मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा कुछ महीनों तक अत्यधिक होती है, जबकि शेष वर्ष जल अभाव बना रहता है। अपर्याप्त भंडारण और प्रबंधन के कारण यह मौसमी जल स्थायी उपलब्धता में परिवर्तित नहीं हो पाता। चेन्नई और केप टाउन जैसे शहर इस विरोधाभास के प्रमुख उदाहरण हैं, जहाँ बाढ़ और सूखा एक ही वर्ष में देखने को मिलते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें लगातार चेतावनी देती रही हैं कि मीठे जल का संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और वैश्विक शांति से भी गहराई से जुड़ा है। जल की कमी आज संघर्ष, प्रवासन और आजीविका संकट का एक उभरता कारण बन रही है।

अंततः, मीठे जल का संकट मानवता के सामने खड़ी सबसे बड़ी साझा चुनौतियों में से एक है। यह स्पष्ट है कि यह समस्या केवल प्राकृतिक सीमाओं की नहीं, बल्कि मानव निर्मित नीतिगत और प्रबंधन विफलताओं की भी है। यदि समय रहते सतत जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, आर्द्रभूमि संरक्षण, समावेशी जल शासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी जाए, तो इस संकट को अवसर में बदला जा सकता है। जल सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल पर्यावरण संरक्षण का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा से जुड़ा अनिवार्य दायित्व है।

भारत की सड़कों पर ट्रैफ़फिक कानून बनाम लापरवाही- क़्या ट्रैफिक कानून हार रहा है?पैसा, पहुंच,पहचान,दबंगई जीत रही है? -लोकतंत्र,जनसंख्या और ट्रैफिक अनुशासन का गहन विश्लेषण

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के हालिया आंकड़े सड़क सुरक्षा,पर्यावरण संरक्षण और विधि शासन के लिए गंभीर चुनौती है।

ट्रैफिक अधिनियमों का सख़्ती से क्रियान्वयन नहीं करना यह केवल प्रशासनिक शिथिलता का प्रश्न नहीं,बल्कि शासकीय मानसिकता,तकनीकी ढांचे, राजनीतिक इच्छाशक्ति और नैतिक अनुशासन का भी मुद्दा है –**एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र**

वैश्विक स्तरपर भारत आज 142.6 करोड़ से अधिक आबादी वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।इतनी विशाल जनसंख्या,विविध सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ ,तीव्र शहरीकरण और तेजी से बढ़ते मोटर वाहनों के बीच कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना किसी भी सरकार के लिए असाधारण चुनौती है।भारत में हजारों केंद्रीय और राज्य कानून लागू हैं और अधिकांश क्षेत्रों में उनका पालन संतोषजनक रूप से होता भी है। किंतु सड़क परिवहन और ट्रैफिक कानूनों का क्रियान्वयन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यवस्था और वास्तविकता के बीच गंभीर अंतर दिखाई देता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहता हूं कि जनता पर लागू प्रमुख सड़क परिवहन कानून और नियमः(1)मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019:यह कानून सड़क सुरक्षा बढ़ाने और नियमों के उल्लंघन (जैसे- बिना हेलमेट /सीटबेल्ट,शराब पीकर गाड़ी चलाना) पर भारी जुर्माने के लिए लागू है।(2)केंद्रीय मोटर वाहन नियम,1989:यह वाहन के तकनीकी मानकों (जैसे- प्रदूषण, लाइट,सुरक्षा उपकरण) को निर्धारित करता है।(3) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002: यह राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने और यातायात के सुचारू संचालन को नियंत्रित करता है।(4)सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007:यह माल परिवहन करने वाले वाहकों के नियमों और दायित्वों से संबंधित है।(5)परिवहन परमिट (धारा 66-70): व्यावसायिक वाहनों के लिए वैध परमिट अनिवार्य है।इन अधिनियमों का सख़्ती से क्रियान्वयन नहीं करना यह केवल प्रशासनिक शिथिलता का प्रश्न नहीं है,बल्कि सामाजिक मानसिकता, तकनीकी ढांचे, राजनीतिक इच्छाशक्ति और नैतिक अनुशासन का भी मुद्दा है।भारत में सड़क सुरक्षा का मूल कानूनी ढांचा मोटर व्हीकलस एक्ट पर आधारित है,जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, इन अधिनियमों का उद्देश्य वाहन पंजीकरण,ड्राइविंग लाइसेंस बीमा,फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना है। 2019 में इस कानून में व्यापक संशोधन किए गए,जुर्मानों को बढ़ाया गया,डिजिटल प्रवर्तन को प्रोत्साहित किया गया और राज्यों को अधिक दायित्व सौंपे गए।इसके बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में पंजीकृत लगभग 40.7 करोड़ वाहनों में से 70 प्रतिशत से अधिक वाहन किसी न किसी वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं कर रहे हैं। इनमें प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र,वैध बीमा,फिटनेस सर्टिफिकेट और समय पर पंजीकरणनवीनीकरण जैसी अनिवार्य शर्तें शामिल हैं। केवल लगभग 8 करोड़ वाहन ही पूर्णतः अनुपालन की श्रेणी में आते हैं,जबकि 30 करोड़ से अधिक वाहन अधूरे दस्तावेजों के साथ सड़कों पर चल रहे हैं।इसके अतिरिक्त 2 करोड़ से अधिक वाहन ऐसे हैं जिनका पंजीकरण पहले ही निरस्त किया जा चुका है,किंतु वे डेटाबेस में दर्ज हैं।यह स्थिति केवल प्रशासनिक आंकड़ों कीसमस्या नहीं है;यह सड़क सुरक्षा,पर्यावरण संरक्षण और विधि शासन के लिए गंभीर चुनौती है।भारत में सबसे बड़ी चिंता दोपहिया वाहनों को लेकर है। गैर- अनुपालन वाले वाहनों में लगभग 23.5 करोड़ दोपहिया वाहन शामिल हैं।हेलमेट का उपयोग न करना,तीन-तीन लोगों का बैठना,नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना,बीमा या फिटनेस न होना,ये दृश्य देश के हर छोटे-बड़े शहर में सामान्य हो चुके हैं। महाराष्ट्र के छोटे शहर गोंदिया से लेकर महानगरों तक ट्रैफिक अनुशासन की कमी स्पष्ट दिखाई देती है।सिग्नल तोड़ना,गलत दिशा में वाहन चलाना मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करना, सोशल मीडिया रील्स बनाने के लिए स्टंट करना,ये सब अब केवल अपवाद नहीं रहे,बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रवृत्ति बनते जा रहे हैं।द्वारका की घटना में मृतक की मां द्वारा कही गई बात,कि यह केवल दुर्घटना नहीं बल्कि मानसिकता का प्रश्न है,भारत की सड़क सुरक्षा बहस का केंद्रीय बिंदु है। सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की होड़,तेज रफ्तार को स्टेटस सिंबल मानना,और कानून को चुनौती देने की प्रवृत्ति एक नई पीढ़ी के भीतर उभरती दिखाई देती है।डिजिटलप्लेटफॉर्म पर खतरनाक स्टंट्स के वायरल होने से युवाओं में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए केवल दंड पर्याप्त नहीं; शिक्षा, जागरूकता और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी आवश्यक है।

साथियों बात अगर हम हाल की घटनाओं ने इस संकट को और भी स्पष्ट कर दिया है इसको समझने की करें तो फरवरी 2026 में दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग द्वारा तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से बाइक सवार युवक को टक्कर मारने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह घटना उस समय हुई जब आरोपी कथित रूप से सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के उद्देश्य से वाहन चला रहा था। मृतक युवक की मां का सार्वजनिक बयान इस घटना को महज दुर्घटना नहीं, बल्कि आपराधिक मानसिकता का परिणाम बताता है।उनका दर्द केवल व्यक्तिगत शोक नहीं था;वह एक ऐसी व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह था जहाँ कुछ लोग स्वयं को कानून से ऊपर समझने लगते हैं।इस घटना में आरोपी नाबालिग को किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। भारत में नाबालिगों से संबंधित मामलों का निपटान जुवेंइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन) एक्ट के तहत किया जाता है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों के पुनर्वास और सुधार पर बल देना है, न कि दंडात्मक प्रतिशोध पर। किंतु जब अपराध की प्रकृति गंभीर हो, विशेषकर तब जब उसमें जान का नुकसान हुआ हो, तो समाज में न्याय और दया के बीच संतुलन को लेकर व्यापक बहस शुरू हो जाती है।द्वारका प्रकरण में आरोपी को बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई,जिससे पीड़ित परिवार और आम जनता में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं।इससे पहले पुणे में हुई चर्चित पोर्श दुर्घटना ने भी देश को झकझोरा था। वहाँ भी एक नाबालिग द्वारा तेज रफ्तार वाहन चलाने से गंभीर दुर्घटना हुई थी और आरोपों में साक्ष्य मिटाने की बात सामने आई थी। ऐसे मामलों में प्रश्न केवल व्यक्तिगत अपराध का नहीं, बल्कि अभिभावकीय जिम्मेदारी सामाजिक प्रतिष्ठा, धनबल और प्रभाव के दुरुपयोग का भी है। जब परिवार अपने नाबालिग बच्चों को उच्च क्षमता वाले वाहन चलाने की अनुमति देते हैं, तो यह केवल कानूनी उल्लंघन नहीं बल्कि नैतिक विफलता भी है।

साथियों बात अगर हम भारत में प्रतिवर्ष लाखों सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं इसको समझने की करेंतो,इसमें हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें बताती हैं कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सड़क दुर्घटनाएँ मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक हैं। भारत, जिसकी सड़क नेटवर्क लंबाई विश्व में सबसे अधिक में से एक है, सड़क सुरक्षा के मामले में अभी भी विकसित देशों से काफी पीछे है। विकसित देशों में सख्त प्रवर्तन,स्वचालित कैमरा प्रणाली, उच्च दंड और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के कारण अनुपालन दर अधिक है।भारत सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक में वाहन डेटाबेस को साफ करने और चरणबद्ध तरीके से गैर- अनुपालन वाहनों को स्वतः डी-रजिस्टर करने का प्रस्ताव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यदि तय समयसीमा के भीतर बीमा,फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते,तो ऐसे वाहनों को स्वतः निष्क्रिय करने की व्यवस्था लागू की जा सकती है। यह कदम केवल तकनीकी सुधार नहीं होगा;यह प्रशासनिकइच्छाशक्ति की परीक्षा भी होगा। सड़क सुरक्षा का प्रश्न केवल कानून या पुलिस तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक संस्कृति का प्रश्न भी है। भारत में कई लोग ट्रैफिक जुर्माने को मामूली खर्च या समझौते का अवसर मान लेते हैं। कुछ स्थानों पर ट्रैफिक विभाग को मलाईदार विभाग कहे जाने का कारण भी यही धारणा है कि प्रवर्तन पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है। जब कानून का पालन कराने वाला तंत्र ही विश्वास खो देता है, तो नागरिक अनुशासन भी कमजोर पड़ जाता है।

साथियों बात कर हम पर्यावरणीय दृष्टि से इस पूरे मुद्दे को समझने की करें तो भी 30 करोड़ से अधिक गैर- अनुपालन वाले वाहनों की उपस्थिति गंभीर चिंता का विषय है। बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के वाहन वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं,जो पहले से ही कई भारतीय शहरों में खतरनाक स्तर पर है। प्रदूषण और सड़क सुरक्षा दोनों ही सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े मुद्दे हैं।यदि भारत को 21वीं सदी में एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना है,तो सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय अनुपालन को प्राथमिकता देनी ही होगी।यह भी ध्यान देने योग्य है कि कानूनों की संख्या पर्याप्त है; समस्या क्रियान्वयन की है। पुलिस बल की कमी,न्यायिक लंबित मामले, तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता और राजनीतिक हस्तक्षेप—ये सभी प्रवर्तन को प्रभावित करते हैं। यदि किसी राज्य में ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों का शीघ्र निपटान नहीं होता, तो दंड का निवारक प्रभाव कम हो जाता है।

साथियों बात अगर हम समाधान के रूप में कुछ ठोस सुझावों को समझने की करें तो, पहला, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावकों के लिए कठोर दंड का अनिवार्य प्रावधान और उसका वास्तविक क्रियान्वयन। दूसरा, सभी वाहनों के लिए डिजिटल अनुपालन ट्रैकिंग और गैर-अनुपालन पर स्वचालित जुर्माना। तीसरा, स्कूल स्तर से सड़क सुरक्षा शिक्षा कोअनिवार्य पाठ्यक्रम में शामिल करना। चौथा,सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ समन्वय कर खतरनाक स्टंट्स के प्रचार पर रोक।

पाँचवाँ ट्रैफिक पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र।भारत का लोकतंत्र विशाल और जीवंत है। परंतु लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं; यह कानून के समक्ष समानता और नागरिक जिम्मेदारी का भी नाम है। जब सड़क पर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है, तो वह केवल व्यक्तिगत जोखिम नहीं लेता; वह दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालता है। द्वारका की घटना में एक मां का आक्रोश हमें याद दिलाता है कि हर दुर्घटना के पीछे एक परिवार का बिखरना छिपा होता है।यदि 70 प्रतिशत वाहन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो यह केवल प्रशासनिक असफलता नहीं बल्कि सामूहिक चेतना का संकट है। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की आकांक्षा के साथ-साथ सामाजिकअनुशासन और विधि-पालन की संस्कृति भी विकसित करनी होगी। सड़क सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित कर केंद्र और राज्यों को समन्वित, तकनीक-समर्थित और पारदर्शी ढांचा अपनाना चाहिए।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तरपर इसको समझने की करें तो अनुभव बताते हैं कि सड़क सुरक्षा सुधार के लिए बहु-स्तरीय रणनीति आवश्यक होती है—कानून का कठोर प्रवर्तन, तकनीकी निगरानी, सड़क अवसंरचना में सुधार, वाहन सुरक्षा मानकों का उन्नयन और नागरिक शिक्षा। भारत में भी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, ई-चालान प्रणाली, और एकीकृत वाहन डेटाबेस जैसी पहलों से सुधार संभव है। परंतु जब तक स्थानीय स्तर पर निरंतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक आंकड़ों में सुधार सीमित रहेगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यह लेख किसी एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक व्यापकआह्वान है।सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वह पैदल यात्री हो, साइकिल सवार, बाइक चालक या कार ड्राइवर सुरक्षा का अधिकार रखता है। कानून का सम्मान और अनुशासन का पालन ही उस अधिकार की रक्षा कर सकता है। यदि सरकार प्रस्तावित ढांचे को सख्ती से लागू करे, वाहन डेटाबेस को शुद्ध करे और गैर- अनुपालन पर वास्तविक दंड सुनिश्चित करे,तो भारत सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है। भारत का भविष्य केवल उसकी जनसंख्या, अर्थव्यवस्था या तकनीकी क्षमता से नहीं तय होगा; वह इस बात से भी तय होगा कि वह अपने नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेता है। सड़क पर अनुशासन, कानून का निष्पक्ष प्रवर्तन और सामाजिक जिम्मेदारी—ये तीनों मिलकर ही उस सुरक्षित और जिम्मेदार भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसकी कल्पना एक सशक्त लोकतंत्र करता है।

फरवरी की यह गर्मी नहीं आम, फूड चेन पर पड़ सकता है असर, सेहत पर भी खतरा

पुनीत उपाध्याय

फरवरी को सर्दी का महीना माना जाता है लेकिन तापमान को लेकर अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलने लगा है। तपिश गर्मी का अहसास कराने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 16 फरवरी को साल का सबसे गर्म दिन रहा। सुबह की ठंड कम हो रही है और कोहरा मुश्किल से दिख रहा है। दिन का तापमान भी 30 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है। ऐसी गर्मी आम नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में हाल में प्रकाशित एक आलेख के अनुसार चल रहे सर्दियों के मौसम के बावजूद मुंबई में असामान्य रूप से ज़्यादा तापमान में तप रहा है पिछले हफ़्ते अधिकतम तापमान लगातार सामान्य से 3.4 डिग्री ज़्यादा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान में हालिया बढ़ोतरी का कारण पूर्वी हवाओं का आना या समुद्र के बजाय ज़मीन की तरफ़ से आने वाली गर्म हवाओं को बताया है।

आईएमडी के वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से निचले लेवल पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं जो ज़मीन से गर्म हवाओं के आने का इशारा है। इससे पिछले हफ़्ते टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में आमतौर पर अरब सागर से आने वाली ठंडी हवाएं चलती हैं। ज़मीन पानी के मुकाबले तेज़ी से गर्म होती है और अंदरूनी इलाकों से आने वाली हवाएं गर्म सूखी हवा लाती हैं जिससे दिन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस सीज़न में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कम देखे गए हैं. ये वे वेदर सिस्टम हैं जो आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में बादल, बारिश या स्नोफॉल लाते हैं और वेस्टर्न इंडिया में टेम्परेचर कम करने में मदद करते हैं। साल 2025 की फरवरी 125 साल में सबसे गर्म महीना था। इससे पहले 2024 को 1901 के रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल घोषित किया गया था। एक्सपर्ट के अनुसार तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी लोगों की सेहत पर भी असर डाल सकती है। इसलिए बढ़ते तापामान के लिए बेहतर अर्बन प्लानिंग, ज़्यादा ग्रीन कवर और बेहतर वॉटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बेहतर अर्ली वॉर्निंग सिस्टम भी अब जरुरी हो गया है।

जानिए क्या कहते हैं आंकडे

डाउन टू अर्थ में छपे एक अन्य आलेख के अनुसार देशभर मे 36 में से 27 शहरों में फरवरी के पहले 15 दिनों के दौरान अधिकतम दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। रात का तापमान यानी न्यूनतम तापमान भी ऊंचा रहा। 20 राज्यों में पहले 15 दिनों में से कम से कम 10 दिनों तक रात का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। उत्तर भारत में बेमौसमी गर्मी का असर खास तौर पर अधिक स्पष्ट रहा। यहां 27 में से 15 शहरों में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किए गए। आमतौर पर कड़ाके की सर्दी के लिए पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में मौसमी पैटर्न से यह बड़ा अंतर था। नई दिल्ली, जयपुर, जम्मू, हिसार, लुधियाना, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों में अधिकतम और रात का तापमान इस समय के औसत से कई डिग्री अधिक रहा और कई बार 25 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया।

विशेषज्ञों के अनुसार तेज गर्मी से गेहूं की फसल समय से पहले पक सकती है। इसके उत्पादन में कमी आ सकती है। 2022 के मार्च महीने में लू के कारण गेहूं फसल पर असर पड़ा था। सरसों, चना, मसूर और मटर समय से पहले फूल दे सकती हैं जिससे फलियों का विकास कमजोर रहेगा। पैदावार घट सकती है। गर्म परिस्थितियां चेंपा और अन्य रस चूसने वाले कीटों की तेजी से वृद्धि के लिए भी अनुकूल हो सकती हैं।आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, फूलगोभी, पत्तागोभी और मटर जैसी सब्जी फसलें भी कंद बनने, गांठ विकसित होने, फूल आने और फल लगने जैसे महत्वपूर्ण चरणों में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं। पशुधन और पोल्ट्री में हीट स्ट्रेस बढ़ सकता है। चारे का सेवन घट सकता है, दूध और अंडा उत्पादन में कमी आ सकती है। बीमारियों का भी खतरा बढ़ सकता है।

रोबोडॉग से परे: भारतीय उच्च शिक्षा का खोखलापन

(प्रमाणन की होड़ में दम तोड़ती अकादमिक गुणवत्ता)

— डॉ. प्रियंका सौरभ

गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रोबोडॉग के प्रदर्शन से जुड़ा हालिया विवाद सोशल मीडिया और मुख्यधारा मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय बना। सतह पर यह मामला उपयुक्तता, प्राथमिकताओं या कैंपस संस्कृति से जुड़ा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में वर्षों से पनप रहे एक गहरे और संरचनात्मक संकट का केवल एक लक्षण है। समस्या रोबोडॉग नहीं है। समस्या यह है कि हमारे विश्वविद्यालय धीरे-धीरे क्या बनते चले गए हैं।

पिछले दो दशकों में भारत में उच्च शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। निजी विश्वविद्यालयों, स्ववित्तपोषित कॉलेजों और डिग्री संस्थानों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। इस विस्तार को अक्सर "शिक्षा तक पहुँच बढ़ने" और "जनसांख्यिकीय लाभ" के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन जब यह विस्तार समानांतर नियमन, अकादमिक कठोरता और जवाबदेही के बिना हुआ, तो इसकी क़ीमत गुणवत्ता को चुकानी पड़ी। परिणाम यह हुआ कि मात्रा बढ़ी, पर गुणवत्ता लगातार गिरती चली गई।

आज देश के अधिकांश—हालाँकि सभी नहीं—निजी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज शिक्षा के केंद्र कम और डिग्री वितरण केंद्र अधिक बन गए हैं। शिक्षा एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लेन-देन बनती जा रही है—पैसे के बदले डिग्री। उपस्थिति, अकादमिक भागीदारी, प्रयोगशाला कार्य और बौद्धिक अनुशासन जैसी बातें अब अनिवार्य नहीं रहीं, बल्कि समझौते के दायरे में आ गई हैं। जो कभी उच्च शिक्षा में गैर-समझौतावादी हुआ करता था, वह अब लचीला, कमजोर और विकृत हो चुका है।

यह गिरावट विशेष रूप से उन विषयों में चिंताजनक है जहाँ कठोरता अनिवार्य है। सैद्धांतिक पढ़ाई का कमजोर होना एक बात है, लेकिन विज्ञान शिक्षा का खोखला हो जाना कहीं अधिक गंभीर है। आज स्थिति यह है कि छात्र बिना नियमित कक्षाओं में गए और बिना प्रयोगशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण लिए विज्ञान जैसे विषयों में स्नातक और परास्नातक डिग्रियाँ प्राप्त कर रहे हैं। प्रयोगात्मक कार्य—जो कभी वैज्ञानिक प्रशिक्षण की रीढ़ हुआ करता था—अब औपचारिकता बनकर रह गया है। डिग्रियाँ तो दी जा रही हैं, लेकिन दक्षता सुनिश्चित नहीं की जा रही।

इस खोखलेपन के परिणाम तब स्पष्ट होते हैं जब छात्र नौकरी के लिए सामने आते हैं। रसायन विज्ञान में परास्नातक छात्र बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाएँ नहीं समझा पाता। कॉमर्स स्नातक डेबिट और क्रेडिट की मूल अवधारणा स्पष्ट नहीं कर पाता। प्रबंधन की डिग्री रखने वाला छात्र समस्या-समाधान और आलोचनात्मक सोच में कमजोर दिखाई देता है। ये कोई इक्का-दुक्का उदाहरण नहीं, बल्कि उद्योग जगत द्वारा बार-बार देखी जा रही सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं।

स्वाभाविक रूप से इससे छात्रों और अभिभावकों में निराशा पैदा होती है। वर्षों की पढ़ाई और भारी आर्थिक निवेश के बावजूद जब रोजगार नहीं मिलता, तो सवाल उठते हैं। माता-पिता यह पूछने में बिल्कुल सही होते हैं कि पढ़ाई के बाद भी बच्चा बेरोज़गार क्यों है। अक्सर इस असंतोष का निशाना सरकार बनती है, जिस पर रोजगार सृजन न कर पाने का आरोप लगाया जाता है। हालाँकि रोजगार सृजन एक नीतिगत चुनौती है, लेकिन यह विमर्श एक असहज सच्चाई को नज़रअंदाज़ कर देता है—कि बड़ी संख्या में स्नातक वास्तव में रोजगार-योग्य ही नहीं हैं।

यहीं से मूल प्रश्न जन्म लेता है। यदि छात्रों में आवश्यक ज्ञान और कौशल नहीं है, तो उन्हें योग्य घोषित करने वाली डिग्रियाँ उन्हें कैसे मिल गईं? ऐसी संस्थाओं को बिना अकादमिक गुणवत्ता सुनिश्चित किए प्रमाणपत्र बाँटने की अनुमति किसने दी? इसका उत्तर हमें उच्च शिक्षा के नियामक ढाँचे में मिलता है।

भारत में उच्च शिक्षा की देखरेख कई मंत्रालयों, विभागों और नियामक संस्थाओं द्वारा की जाती है, जिनका घोषित उद्देश्य मानकों की रक्षा, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और अकादमिक ईमानदारी बनाए रखना है। मान्यता प्रणालियाँ, निरीक्षण, मूल्यांकन और अकादमिक ऑडिट इसी उद्देश्य से बनाए गए थे। लेकिन व्यवहार में ये प्रक्रियाएँ अक्सर वास्तविक मूल्यांकन की बजाय औपचारिक अनुष्ठान बनकर रह गई हैं। निरीक्षण प्रायः पूर्व-निर्धारित होते हैं। दस्तावेज़ औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सजाए जाते हैं। इमारतों और बुनियादी ढाँचे को शिक्षण गुणवत्ता पर प्राथमिकता दी जाती है। अनुपालन को सीखने के परिणामों से ऊपर रखा जाता है। छात्रों का वास्तविक अकादमिक अनुभव, शिक्षण की गुणवत्ता, परीक्षा की कठोरता और जिज्ञासा की संस्कृति—इन पर गंभीर और निरंतर निगरानी शायद ही होती है। नतीजतन, संस्थान शिक्षा सुधारने के बजाय नियामकों को "मैनेज" करना सीख लेते हैं।

इस नियामक शिथिलता ने एक दुष्चक्र को जन्म दिया है—संस्थान न्यूनतम अकादमिक जवाबदेही के साथ चलते रहते हैं, नियामक निगरानी का आभास बनाए रखते हैं, और डिग्रियाँ लगातार जारी होती रहती हैं। इस व्यवस्था की क़ीमत न तो संस्थान चुकाते हैं, न ही नियामक—बल्कि छात्र, नियोक्ता और समाज चुकाता है।

विडंबना यह है कि एक ओर उद्योग जगत योग्य मानव संसाधन की कमी की शिकायत करता है, वहीं दूसरी ओर देश शिक्षित बेरोज़गारी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। यह कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है जहाँ प्रमाणपत्र को क्षमता से ऊपर रखा गया है। कंपनियाँ नए कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करने पर भारी ख़र्च करने को मजबूर हैं, जबकि युवा पेशेवर आत्मविश्वास की कमी और करियर ठहराव से जूझते हैं।

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार वे ईमानदार और प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो अक्सर विकल्पों की कमी या भ्रामक ब्रांडिंग के कारण औसत संस्थानों में दाख़िला ले लेते हैं। वे मेहनत करते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन अंततः उन्हें अपनी काबिलियत से ज़्यादा अपनी मार्कशीट पर दर्ज संस्थान के नाम का बोझ उठाना पड़ता है। उनकी व्यक्तिगत योग्यता संस्थागत विश्वसनीयता की कमी में दब जाती है। यह केवल अन्याय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा की बर्बादी है।

यह स्वीकार करना होगा कि भारत में आज भी कुछ उच्च-गुणवत्ता वाले संस्थान मौजूद हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन वे अपवाद हैं, नियम नहीं। उल्लेखनीय है कि बारहवीं तक की स्कूली शिक्षा आज भी अपेक्षाकृत अधिक संरचित और नियंत्रित है। जैसे ही छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है, निगरानी ढीली पड़ जाती है और अपेक्षाएँ धुंधली हो जाती हैं।

यदि इस प्रवृत्ति को समय रहते नहीं रोका गया, तो इसके दीर्घकालिक परिणाम गंभीर होंगे। डिग्रियों का सामाजिक और आर्थिक मूल्य घटेगा। उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक विश्वास कमजोर होगा। योग्यता और औसतपन के बीच का अंतर और अधिक अस्पष्ट होता जाएगा। "हर गली में विश्वविद्यालय" जैसे वाक्य व्यंग्य नहीं, बल्कि यथार्थ का वर्णन बन जाएंगे—जहाँ विश्वविद्यालय तो हर जगह होंगे, पर शिक्षा नहीं।

अब सुधार का समय है—और वह सुधार ईमानदार और कठोर होना चाहिए। नियामक संस्थाओं को बॉक्स-टिकिंग से आगे जाकर परिणाम-आधारित, पारदर्शी और अप्रत्याशित मूल्यांकन अपनाना होगा। शिक्षण की गुणवत्ता, सीखने के परिणाम, छात्र सहभागिता और मूल्यांकन की ईमानदारी को इमारतों और विज्ञापनों से ऊपर रखना होगा।

संस्थानों की जवाबदेही तय करनी होगी। जो कॉलेज और विश्वविद्यालय लगातार अकादमिक रूप से असफल हो रहे हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए—सीटों में कटौती, पाठ्यक्रम निलंबन या मान्यता रद्द करने तक। उच्च शिक्षा ऐसा व्यवसाय नहीं हो सकता जहाँ असफलता की कोई क़ीमत न चुकानी पड़े।

छात्रों और अभिभावकों को भी अधिक सजग होना होगा। केवल मार्केटिंग, बुनियादी ढाँचे और ब्रांडिंग के आधार पर निर्णय लेना भविष्य के साथ समझौता है। शिक्षा कोई साधारण ख़रीद नहीं, बल्कि बौद्धिक और व्यावसायिक विकास में निवेश है—और ग़लत निर्णयों के दूरगामी परिणाम होते हैं।

अंततः, उच्च शिक्षा का उद्देश्य डिग्री बाँटना नहीं, बल्कि सोचने-समझने वाले, सक्षम और ज़िम्मेदार नागरिक तैयार करना है। जब तक यह मूल उद्देश्य पुनः स्थापित नहीं होता, तब तक रोबोडॉग जैसे विवाद आते रहेंगे—कुछ समय के लिए शोर मचाएँगे और फिर शांत हो जाएँगे—जबकि असली संकट जस का तस बना रहेगा।

हमें सजावटी सुधार नहीं, बल्कि प्रणालीगत आत्ममंथन चाहिए। क्योंकि शिक्षा का संकट कभी केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता—वह चुपचाप राष्ट्र का भविष्य गढ़ता है।

(डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), कवयित्री एवं सामाजिक चिंतक

झारखंड में गुंडों की समानांतर सरकार: आदित्य साहु , भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

नगर निकाय चुनाव से डर रही है सत्ता

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला ,लौह नगरी जमशेदपुर में आयोजित प्रेस-वार्ता में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने निकाय, परिषद चुनाव के पहले राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा शुरू से ही नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव कराने की नहीं थी और पिछले तीन वर्षों से जानबूझकर चुनाव लटकाए गए।

उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राज्य की 48 नगर निकायों में आंदोलन और प्रदर्शन कर सरकार को झुकने पर मजबूर किया। दबाव में आकर सरकार चुनाव करा रही है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं है।दलीय आधार और ईवीएम से भाग रही है सरकार प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 2018 में दलीय आधार पर और ईवीएम से चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार सरकार को हार का भय सता रहा है। सरकार जानती है कि छह वर्षों में शहर और गांव- कहीं विकास नहीं हुआ। इसलिए दलीय आधार और ईवीएम से चुनाव कराने से भाग रही है। 26 साल बाद फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव कराना लोकतंत्र को पीछे ले जाने जैसा है।

अपराधियों के सहारे चुनाव की साजिश

आदित्य साहू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गुंडों और अपराधियों के बल पर चुनाव प्रभावित करना चाहती है। भाजपा ने चुनाव आयोग से केंद्रीय बल की तैनाती और हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की थी, लेकिन सरकार इससे भी बच रही है ।चक्रधरपुर में धमकी का मामला

आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि चक्रधरपुर में भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह गागराई को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई है। पोस्टर चिपकाकर डराने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को भी चुनाव प्रचार से रोकने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। झारखंड में अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है।

कड़िया मुंडा को धमकी पर सरकार मौन

भाजपा अध्यक्ष ने वरिष्ठ आदिवासी नेता एवं पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा को मिली धमकी का भी मुद्दा उठाया। कहा कि आठ बार सांसद रहे, झारखंड आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे ऐसे वरिष्ठ नेता को फोन पर धमकी दी जा रही है और सरकार खामोश है। आखिर सुरक्षित कौन है इस राज्य में।

अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई की मांग तेज

आसपास के जिलों में आपूर्ति की चर्चा, प्रशासन से सख्त कदम उठाने की अपील

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेला: राउरकेला पुलिस द्वारा हाल के दिनों में स्क्रैप माफिया, गांजा, अफीम, जुआ-सट्टा और म्यूल अकाउंट जैसे आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ चलाए गए लगातार अभियानों के बाद अब आम जनता की नजर अवैध देशी और कथित नकली विदेशी शराब के कारोबार पर संभावित कार्रवाई की ओर टिक गई है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में इस विषय को लेकर चर्चा तेज हो गई है तथा लोगों द्वारा प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है।

स्थानीय स्तर पर यह बात सामने आ रही है कि राउरकेला क्षेत्र से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में शराब की आपूर्ति सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़ और बरगढ़ जिलों तक किए जाने की चर्चा है। हालांकि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि इस प्रकार की गतिविधियों पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे सरकारी राजस्व को नुकसान होने के साथ-साथ आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

सूत्रों के अनुसार, इस अवैध कारोबार से जुड़े कुछ नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय बताए जा रहे हैं। नागरिकों का मानना है कि जिस तरह अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकारात्मक परिणाम मिले हैं, उसी प्रकार अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध भी विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है।

जानकारों का कहना है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नियमित निगरानी, खुफिया तंत्र की सक्रियता और समय-समय पर जांच अभियान जरूरी है। साथ ही, किसी भी प्रकार की शिकायत या साक्ष्य सामने आने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नागरिकों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था मजबूत बनी रहे।

प0 सिंहभूम जिले में डायन के नाम पर पेट्रोल डाल मासुम व महिला की कूरतम हत्या

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

चाईबासा , झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से अंधविश्वास और क्रूरता की एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कलाईया गांव (कुदासाई टोला) में मंगलवार की देर रात डायन होने के संदेह में एक महिला और उसके महज छह महीने के मासूम बच्चे को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया।

इस भीषण वारदात में मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतका का पति झुलसी हुई हालत में भागकर जान बचाने में सफल रहा।

घटना मंगलवार रात करीब नौ बजे की है। पीड़ति कोल्हान सिंकु अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंकु (32) और दो बच्चों के साथ कमरे में सो रहा था।

उसी घर के दूसरे कमरे में उसकी पहली पत्नी जानी सिंकु भी बच्चों के साथ थी। इसी दौरान गांव का ही रासिका बिरुवा अपने भाइयों और करीब 8-9 अन्य लोगों के साथ कोल्हान के घर पहुंचा और उसे जबरन बाहर निकाला।

आरोप है कि रासिका बिरुवा ने कोल्हान की दूसरी पत्नी ज्योति पर डायन होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कोल्हान ने हाथ जोड़कर मामले का फैसला पंचायत में करने की गुहार लगाई, लेकिन हमलावरों ने एक न सुनी।

देखते ही देखते आरोपियों ने ज्योति पर पेट्रोल उड़ेल दिया और माचिस जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया। इसमें महिला और मासूम बुरी तरह झुलस कर जल गए।

आग की लपटों से घिरी ज्योति ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गोद में सो रहे छह माह के नवजात को बचाने के लिए उसे जमीन पर गिरा दिया और खुद घर के अंदर भागकर कंबल से आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन पेट्रोल की वजह से आग और भड़क उठी और ज्योति ने वहीं दम तोड़ दिया। दुर्भाग्यवश, जमीन पर गिरा मासूम भी आग की चपेट में आ गया और उसकी भी जलकर मौत हो गई।

इस भयानक मंजर को देख कोल्हान की पहली पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग निकली। बुधवार सुबह जब घायल कोल्हान सिंकु ने पुलिस को आपबीती सुनाई, तो प्रशासन हरकत में आया।

जगन्नाथपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रफायल मुर्मु के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रासिका बिरुवा सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है ।गिरफ्तार आरोपियों के जेना बिरूवा 19,सोना बिरूवा36, डेलगा सिकुं20 तथा सुकुमारी सामिल है ।

पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए अन्य लोगों से पूछताछ जारी है और दो-तीन और महिलाओं की संलिप्तता की पुष्टि हुई है जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए रांची से राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफ एस एल की टीम को बुलाया गया है, ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें। मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर बासुदेव मुंडा, थाना प्रभारी मिलन करमाली और धीरज कुमार यादव की एक विशेष टीम गठित की गई है।

विधानसभा में बीजद-भाजपा में टकराव, इनपुट सब्सिडी को लेकर खींचतान

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : विधानसभा में बीजेडी-बीजेपी इनपुट सब्सिडी पर टकराव। इनपुट सब्सिडी पर सप्लाई मिनिस्टर के जवाब के बाद विपक्षी पार्टी के डिप्टी लीडर ने सरकार पर निशाना साधा। प्रसन्ना आचार्य ने पूछा कि वे 800 रुपये की जगह 731 रुपये क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ऐलान किया था कि वह किसानों को 800 रुपये देगी, लेकिन वह 731 रुपये क्यों दे रही है ।किसानों को 69 रुपये से क्यों वंचित रखा जा रहा है ?

प्रसन्ना आचार्य की शिकायत के बाद BJP के अश्विनी सारंगी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 100 रुपये का ऐलान नहीं किया, वे 800 रुपये की बात कैसे कर रहे हैं। हमने चुनाव के दौरान 3100 रुपये देने की बात कही थी, और हम दे रहे हैं।

हालांकि, BJD MLA रोमंच रंजन विशाल ने पूछा था कि किसानों को कितनी इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। जवाब में सप्लाई मिनिस्टर ने कहा कि किसानों को 800 रुपये नहीं, बल्कि 731 रुपये इनपुट सब्सिडी मिल रही है। केंद्र 2369 रुपये में धान खरीदता है, राज्य सरकार 731 रुपये दे रही है। अगर सरकार 800 रुपये देती, तो वह 3169 रुपये में धान खरीदती। इस बारे में, मिनिस्टर के जवाब के बाद BJD ने सरकार पर निशाना साधा है।

संयुक्त कार्यकारी पत्रकार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने नवीन पटनायक को निमंत्रण दिया है

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : संयुक्त कार्यकारी पत्रकार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने नवीन पटनायक को निमंत्रण दिया है। संयुक्त कार्यकारी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष रजनीकांत सामंतराय की देखरेख में, एक प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक से मुलाकात की और उन्हें दिल्ली में आयोजित भारतीय मीडिया कांग्रेस के दूसरे सत्र के लिए निमंत्रण दिया। नवीन पटनायक ने संयुक्त कार्यकारी पत्रकार संघ के प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रतिनिधिमंडल में रजनीकांत सामंतराय, संजय दास, प्रद्युम्न दास, प्रसन्ना पृस्टी, मनोरंजन शासमल और पूर्णचंद्र साहू शामिल थे। दिल्ली में आयोजित भारतीय मीडिया कांग्रेस में भाग लेने के लिए पूरे भारत से पत्रकार एकत्र हो रहे हैं। आईएमसी राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकार संघों के बीच समन्वय के लिए एक मंच है। आईएमसी और ओयूडब्ल्यूजे हमेशा पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह दिल्ली यात्रा विकसित ओडिशा 2036 के लिए पत्रकारों की भूमिका पर चर्चा करने के लिए है।

ग्रामीण पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ओडिशा में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के साथ एएमयू की स्थापना की गई है। आईएमसी और ओयूडब्ल्यूजे हमेशा पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह दिल्ली यात्रा विकसित ओडिशा 2036 के लिए पत्रकारों की भूमिका पर चर्चा करने के लिए है।

माता-पिता क़े परित्याग पर कठोर कानून- संवैधानिक संतुलन, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और भारत के लिए नीतिगत रोडमैप सर्वोच्च प्राथमिकता

बदलती भारतीय संस्कृति, प्रवासी संतानों की जिम्मेदारी और बुजुर्ग माता-पिता का संरक्षण-सशक्त पांच समकालीन कानूनों की आवश्यकता

भारत में बुजुर्ग माता-पिता क़ा परित्याग, उपेक्षा व अकेले छूटते जाना,यह केवल भावनात्मक प्रश्न नहीं,बल्कि सामाजिक न्याय,मानवाधिकार व केंद्र,राज्य क़े उत्तरदायित्व-व्यवस्था से जुड़ा विषय है -

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत की सभ्यता की मूल आत्मा मातृदेवो भव,पितृदेवो भव के आदर्शमेंनिहित रही है ।भारतीय परिवार व्यवस्था केवल रक्त संबंधों का ढांचा नहीं,बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व,त्याग, सह- अस्तित्व और पीढ़ियों के परस्पर सम्मान पर आधारित एक सामाजिक अनुबंध है। किंतु 21वीं सदी के तीव्र वैश्वीकरण, शहरीकरण और प्रवासन के युग में यह पारंपरिक ताना-बाना तेज़ी से बदल रहा है। छोटे शहरों और गांवों से निकलकर युवा मेट्रो सिटीज़ और विदेशों में बस रहे हैं।आर्थिक प्रगति, करियर अवसर और वैश्विक एक्सपोज़र निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन हैं,परंतु इन उपलब्धियों की छाया में मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह महसूस कर रहा हूं कि एक गंभीर सामाजिक संकट भी उभर रहा है, भारत में अकेले छूटते जा रहे बुजुर्ग माता -पिता की उपेक्षा ! यह केवल भावनात्मक प्रश्न नहीं,बल्कि सामाजिक न्याय,मानवाधिकार और राज्य की उत्तरदायित्व-व्यवस्था से जुड़ा विषय है ।भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग साढ़े तीन करोड़ बताई जाती है। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके माता-पिता भारत में ही रहते हैं। प्रारंभिक वर्षों में प्रवासी संतानें आर्थिक सहायता और नियमित संपर्क बनाए रखती हैं,परंतु समय बीतने के साथ पारिवारिक लगाव का क्षरण होने लगता है।अनेक मामलों में बुजुर्ग माता-पिता आर्थिक,शारीरिक और भावनात्मक रूप से असुरक्षित स्थिति में रह जाते हैं। पिछले वर्ष ऐसे 500 से अधिक मामले सामने आए, जिनमें अकेले रह रहे माता- पिता की मृत्यु अत्यंत दुखद परिस्थितियों में हुई और संतान समय पर लौटकर भी नहीं आई। दिल्ली और इंदौर जैसे शहरों में सामने आई घटनाओं ने समाज को झकझोर दिया है ।यह स्थिति केवल व्यक्तिगत नैतिक विफलता नहीं है; यह एक संरचनात्मक शून्य की ओर संकेत करती है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर संक्रमण, बढ़ती जीवनशैली लागत,विदेशों में व्यावसायिक दबाव और सांस्कृतिकअनुकूलन के कारण संतानें अक्सर अपने मूल दायित्वों से दूर हो जाती हैं। परिणामस्वरूप, माता-पिता सामाजिक अलगाव, आर्थिक निर्भरता और मानसिक अवसाद का सामना करते हैं ।हाल ही में राज्यसभा के बजट सत्र में राधा मोहन अग्रवाल साहब ने यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया जो तारीफ़ ए काबिल है, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो प्रवासी भारतीय अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते, उनके पासपोर्ट रद्द किए जाएँ। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विदेश जाने से पहले संतान से हलफनामा लिया जाए,जिसमें वे अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा माता-पिता को देने, उनके लिए केयरटेकर और बीमा की व्यवस्था करने तथा सप्ताह में कम से कम एक बार संपर्क बनाए रखने का वचन दें। छह माह में सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन जमा कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई, जिसके आधार पर यह प्रमाणित हो कि संतान अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही है ।यह प्रस्ताव कठोर अवश्य है, परंतु इसके पीछे निहित भावनात्मक और नैतिक तर्क अत्यंत सशक्त है संतान की सफलता के पीछे माता-पिता का त्याग, तपस्या और कभी-कभी संपत्ति तक का बलिदान होता है। राज्य की सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं का भी योगदान रहता है। ऐसे में यदि संतान अपनी जड़ों को भूल जाए, तो यह केवल पारिवारिक विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन है।

साथियों बात अगर हम वर्तमान कानूनी ढांचा और उसकीसीमाएँ इसको समझने की करें तोभारत सरकार ने वर्ष 2007 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट,2007 (माता-पिता और वरिष्ठनागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007) लागू किया था। इस कानून का उद्देश्य संतानों पर माता-पिता के भरण-पोषण की कानूनी जिम्मेदारी निर्धारित करना था। अधिनियम के अंतर्गत माता- पिता ट्रिब्यूनल में आवेदन कर आर्थिक सहायता का आदेश प्राप्त कर सकते हैं ।किन्तु व्यावहारिक स्तरपर यह कानून कई कारणों से दंतहीन सिद्ध हुआ है। प्रथम, शिकायत दर्ज कराने की पहल स्वयं बुजुर्गों को करनी होती है, जो सामाजिक संकोच, भावनात्मक दबाव या शारीरिक अक्षमता के कारण अक्सर संभव नहीं हो पाती। द्वितीय, प्रवासी संतानें विदेश में होने के कारण आदेशों के क्रियान्वयन में प्रशासनिक कठिनाइयाँ आती हैं। तृतीय, कानून मुख्यतःआर्थिक सहायता तक सीमित है;इसमेंभावनात्मक और देखभाल संबंधी दायित्वों का स्पष्ट प्रवर्तन तंत्र नहीं है। परिणामतः समस्या की गंभीरता के अनुरूप प्रभावी समाधान नहीं मिल पाता। इसीलिए ही जरूरत आन पड़ी है कि कुछ मेरे द्वारा सुझाए के पांच कानून को विधायक के रूप में संसद में पेश करो ने तुरंत पारित करने की प्रक्रिया की जाए यह सुझाव में इस आर्टिकल के माध्यम से नीति निर्धारकों, राज्यसभा लोकसभा सांसदों,प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कार्यालयों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं।

साथियों बातें कर हम मेरे द्वारा सुझाए गए पांच प्रस्तावित नए कानून की आवश्यकता कुछ समझने की करें तो समस्या की गंभीरता को देखते हुए एक समकालीन,वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप और तकनीकी रूप से सक्षम कानून कीआवश्यकता अनुभव की जा रही है। इसके लिए निम्नलिखित संभावित नाम प्रस्तावित किए जा सकते हैं(1)भारतीय माता-पिता संरक्षण एवं सम्मान अधिनियम, 2026(2)वरिष्ठ नागरिक वैश्विक उत्तरदायित्व अधिनियम, 2026 (3) माता-पिता भरण-पोषण अनिवार्यता एवं दायित्व अधिनियम, 2026 (4) भारतीय पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं संरक्षण अधिनियम, 2026 (5) प्रवासी संतान अभिभावक संरक्षण अधिनियम, 2026, इन नामों में केवल दंडात्मक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि संरक्षण, सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना झलकती है। किसी भी नए कानून का उद्देश्य परिवारों को तोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें पुनःजोड़ना होना चाहिएकानूनों की संभावित मुख्य विशेषताएँ- एक प्रभावी कानून बहुस्तरीय होना चाहिए,आर्थिक, प्रशासनिक तकनीकी और नैतिक आयामों को समाहित करते हुए। (1) विदेश या किसी मेट्रो या किसी भी छोटी सिटीज में रहने वाली संतान के लिए अनिवार्य वार्षिक आर्थिक योगदान की व्यवस्था। यह योगदान आय के अनुपात में निर्धारित हो सकता है,जिससे आर्थिक असमानता का संतुलन बना रहे। (2) माता-पिता की शिकायत पर त्वरित न्यायिक तंत्र विशेष ट्रिब्यूनल या फास्ट-ट्रैक व्यवस्था हो,जहाँ 60 से 90 दिनों के भीतर निर्णय दिया जाए।(3) एक राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल, जहाँ बुजुर्ग अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। यह पोर्टल सरल भाषा, वीडियो सहायता और हेल्पलाइन से युक्त हो,ताकि तकनीकी रूप से कमज़ोर वरिष्ठ नागरिक भी इसका उपयोग कर सकें।(4) वेतन या आय से स्वचालित कटौती की कानूनी व्यवस्था।आयकर विभाग और बैंकों के सहयोग से निर्धारित राशि सीधे माता-पिता के खाते में स्थानांतरित की जा सके।(5), गंभीर उपेक्षा की स्थिति में पासपोर्ट निलंबन या वीजा प्रतिबंध। यह प्रावधान अंतिम उपाय के रूप में हो, ताकि दंडात्मक कार्रवाई से पहले सुधार का अवसर मिले हलफनामा और प्रमाणन प्रणाली-छह माह में सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन जमा कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित की जाए अन्यथा सैलरी पर रोक तथा संबंधित व्यक्ति पर क्रिमिनल केस दर्ज करने का आधार माना जाए (6) विदेश जाने से पहले एक अनिवार्य हलफनामा लिया जा सकता है,जिसमें संतान अपने माता-पिता की देखभाल का वचन दे ।इसमेंनिम्नबिंदु शामिल हों, (1)आय का निश्चित प्रतिशत माता-पिता को देना।(2)स्वास्थ्य बीमा औरआवश्यक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना। (3)आवश्यकता पड़ने पर केयरटेकर नियुक्त करना।(4) सप्ताह में कम से कम एक बार यह प्रमाण पत्र माता-पिता द्वारा जारी किया जाए कि उनकी संतान दायित्व निभा रही है। यदि प्रमाण पत्र न दिया जाए,तो संबंधितप्राधिकारी कारण की जांच करे और आवश्यकतानुसार चेतावनी या दंडात्मक कार्रवाई करे।

साथियों बात अगर हम पासपोर्टनिरस्तीकरण का प्रश्न इसको समझने की करें तो,पासपोर्ट रद्द करना एक कठोर कदम है, क्योंकि यह व्यक्ति की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता और रोजगार पर सीधा प्रभाव डालता है ।अतः इसे अंतिम उपाय के रूप में ही रखा जाना चाहिए। प्रारंभिक चरण में चेतावनी, जुर्माना या अस्थायी निलंबन जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। केवल गंभीर और निरंतर उपेक्षा की स्थिति में ही पासपोर्ट निरस्तीकरण का प्रावधान हो। इससे कानून का संदेश सख्त भी रहेगा और बेहतर तरीके से न्यायसंगत भी।

साथियों बात अगर हम इस मुद्दे को संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो (1)अनुच्छेद 21- जीवन और गरिमा का अधिकार- भारतीय संविधानका अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है ।सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर इसे विस्तृत अर्थ में व्याख्यायित किया है जिसमें भोजन, स्वास्थ्य, आश्रय और सम्मान सम्मिलित हैं ।वृद्ध माता-पिता का परित्याग सीधे-सीधे उनके गरिमामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। अतः राज्य का दायित्व बनता है कि वह उनकी रक्षा करे। (2) अनुच्छेद 19 (1) (डी) और 19(1)(जी)- आवाजाही और व्यवसाय की स्वतंत्रता- यदि पासपोर्ट रद्द करने या विदेश यात्रा पर रोक लगाने का प्रावधान किया जाए, तो यह नागरिक की स्वतंत्रता पर अंकुश होगा।

एग्जाम स्ट्रेस से सफलता तक: परीक्षा फोबिया को हराने के आसान उपाय

-सुनील कुमार महला

इन दिनों हमारे देश में परीक्षाओं का दौर चल रहा है और ऐसे समय में बच्चे अक्सर तनाव, अवसाद और डर(एक्जाम फोबिया) का अनुभव करते हैं। परीक्षा को लेकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं-क्या होगा, कैसे होगा, कितने अंक आएंगे, माता-पिता क्या कहेंगे, शिक्षक या पड़ोसी क्या सोचेंगे आदि। लेकिन यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षा जीवन की अंतिम कसौटी नहीं है। प्रतिस्पर्धा अपने स्थान पर उचित है, परंतु प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। सभी की क्षमताएँ और प्रतिभाएँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए तुलना करना कभी भी उचित नहीं होता,यह हमें(माता-पिता , अभिभावकों व शिक्षकों को) समझना चाहिए। किसी में एक गुण होता है तो किसी में दूसरा, इसलिए तुलना के बजाय प्रोत्साहन अधिक आवश्यक है।

बहरहाल, यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि परीक्षा का मौसम आते ही घरों का वातावरण भी बदल जाता है। बोर्ड परीक्षाएँ हों या प्रवेश परीक्षाएँ, लाखों छात्र उम्मीदों और दबाव के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में केवल अधिक पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सही तरीके से पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, जिसमें शरीर, मन और भावनाओं का संतुलन बना रहे। याद रखिए कि परीक्षा के तनाव से निपटने की शुरुआत शरीर से होती है। कई छात्र देर रात तक जागना या भोजन छोड़ना मेहनत समझ लेते हैं, जबकि पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम ही एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति की वास्तविक नींव हैं। पौष्टिक भोजन मस्तिष्क को ऊर्जा देता है और अच्छी नींद पढ़ी हुई जानकारी तथा मुख्य बिंदुओं को याद रखने में सहायक होती है। बड़े पाठ्यक्रम को छोटे-छोटे लक्ष्यों में बाँटना और पढ़ाई के बीच थोड़े विश्राम लेना भी तनाव को कम करता है।

भारतीय परंपरा भी मानसिक संतुलन का महत्व बताती है। योग, प्राणायाम और ध्यान(मेडिटेशन) जैसे सरल अभ्यास तनाव के समय राहत प्रदान कर सकते हैं। जब शरीर शांत होता है, तो मन भी शांत हो जाता है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन शरीर में जमा तनाव(स्ट्रेस) को कम करने में सहायक है, जबकि प्रतिदिन लगभग 10 मिनट का ध्यान मन को स्थिर और स्पष्ट बनाता है, जिससे छात्र घबराहट की बजाय आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कर पाते हैं।

यदि कक्षा का वातावरण ऐसा हो, जहाँ गलती को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाए और रटने के बजाय समझ पर ज़ोर दिया जाए, तो परीक्षा का भय काफी कम हो सकता है। इसके विपरीत, बार-बार तुलना और रैंकिंग तनाव बढ़ा देती है। जब शिक्षक यह संदेश देते हैं कि परीक्षा महत्वपूर्ण है, परंतु जीवन की अंतिम कसौटी नहीं, तो छात्रों में स्वस्थ व सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। घर का माहौल भी उतना ही प्रभाव डालता है। यदि माता-पिता केवल अंकों पर ध्यान देने के बजाय बच्चों के प्रयास, प्रगति और व्यक्तित्व विकास को महत्व दें, तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। परीक्षा परिणाम नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है। जब छात्र स्वयं को केवल अंकों से नहीं, बल्कि अपनी बहुआयामी प्रतिभा से पहचानते हैं, तब वे इस चुनौतीपूर्ण दौर को संतुलन, साहस और गरिमा के साथ पार कर सकते हैं।

परीक्षा को कभी भी फोबिया नहीं बनाना चाहिए और जितना पढ़ा है, उसी पर सकारात्मक रहकर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखें कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जबकि शांत मन, संयम और धैर्य सबसे बड़े गुण हैं। सही खान-पान रखें, पर्याप्त नींद लें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। माता-पिता, अभिभावकों व शिक्षकों को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा यह समझाना चाहिए कि परीक्षा कोई इरावनी चीज़ नहीं है। याद रखिए, असफलता हार नहीं होती, बल्कि एक सीख होती है, जो हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए सबसे ज़रूरी है-स्वयं पर दृढ़ विश्वास रखना।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि परीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवश्य है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं। सही तैयारी, संतुलित दिनचर्या, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ छात्र किसी भी परीक्षा का सामना सहजता से कर सकते हैं। माता-पिता और शिक्षकों का सहयोग, प्रोत्साहन और समझ बच्चों के परीक्षाई तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में परीक्षा-भय किसी विषय की अज्ञानता से अधिक हमारी मानसिक स्थिति और असफलता के डर से उत्पन्न होता है। यह कोई स्थायी समस्या नहीं है; सही समय प्रबंधन, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच के माध्यम से इसे पूरी तरह दूर किया जा सकता है।

अक्सर छात्र परीक्षा को जीवन-मरण का प्रश्न मान लेते हैं, जबकि यह केवल शैक्षणिक मूल्यांकन की एक सामान्य प्रक्रिया है। यदि विद्यार्थी अपनी तैयारी व्यवस्थित रखें और अभिभावक बच्चों की दूसरों से तुलना करना बंद कर दें, तो परीक्षा का बोझ एक रोमांचक चुनौती में बदल सकता है। अंततः, सफलता के लिए मानसिक शांति और स्वयं पर विश्वास उतना ही आवश्यक है, जितना कि पाठ्यक्रम का ज्ञान। इसलिए परीक्षा को डर नहीं, अवसर समझकर शांत मन से आगे बढ़ना ही सफलता का सही मार्ग है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**